नई दिल्ली

01

सितंबर, 2026

मंगलवार

मूल्य : 01 रुपए

पृष्ठ : 08

वर्ष : 14

अंक : 152

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

RNI No. DELMUL/2012/47011

www.timesofpedia.com

Email : timesofpedia@gmail.com

एकदिवसीय में जगह नहीं बना पाने के लिए अपने को जिम्मेदार मानते है सूर्यकुमार 07

संक्षिप्त वार्ता

रैली के लिए नई दिल्ली आने से कार्यकताओं को रोका जा रहा

नई दिल्ली। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) के महासचिव डी. राजा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली में आगामी रैली से पहले उत्तर प्रदेश में पार्टी के नेताओं और कार्यकताओं को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लेकर नजरबंद किया जा रहा है। सीपीआई नेता राजा ने अपने पत्र में बताया कि 1 सितंबर, 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में सीपीआई की अखिल भारतीय रैली प्रस्तावित है, जिसे सरकारी अधिकारियों से पहले ही अनुमति मिल चुकी है।

उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पुलिस, रैली में शामिल होने की तैयारी कर रहे पार्टी सदस्यों को परेशान कर रही है और उन्हें अवैध रूप से हिरासत में ले रही है। सीपीआई नेता राजा ने अलीगढ़, हाथरस, गाज़ियाबाद, संभल, शाहजहाँपुर सहित कई जिलों से ऐसी पुख्ता रिपोर्ट मिलने का जिक्र किया, जहां पुलिस कथित तौर पर कार्यकताओं को दिल्ली की रैली में हिस्सा न लेने की धमकी दे रही है। सीपीआई नेता राजा ने कार्रवाई को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों और राजनीतिक दलों को दिए गए लोकतांत्रिक अधिकारों का खुला उल्लंघन बताया।

सीजेपी के मार्च को रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार

नई दिल्ली। दिल्ली में 5 सितंबर को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के इंडिया गेट मार्च पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई ठोस आधार सामने नहीं आया है, जिससे यह माना जाए कि मार्च के दौरान कोई अप्रिय घटना हो सकती है। कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने सभी पक्षों से कानून के दायरे में रहते हुए शांतिपूर्ण तरीके से काम करने की उम्मीद जताई।

यहां बताते चलें कि सीजेपी ने 5 सितंबर को इंडिया गेट तक मार्च का ऐलान किया है। मार्च पर रोक लगाने की मांग को लेकर एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील डॉ. रिजवान ने कहा कि मार्च की घोषणा सोशल मीडिया के जरिए की गई है, लेकिन उनकी जानकारी के मुताबिक इसके लिए अभी अनुमति नहीं ली गई है।

1 लाख 22 हजार विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए मिलेंगे 25-25 हजार रुपये

भोपाल। कक्षा 12वीं में प्रथम प्रयास में 75 प्रतिशत या अधिक अंक पाने वाले प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों का आधुनिक तकनीक से जुड़ने का सपना जल्द ही पूरा होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश के लगभग 1 लाख 22 हजार विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपये की राशि का अंतरण करेंगे। विद्यार्थियों को यह राशि 1 सितंबर को कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, भोपाल में आयोजित लैपटॉप क्रय के लिये राशि वितरण कार्यक्रम के दौरान प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें डिजिटल तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है।

बारिश और बाढ़ से अनेक राज्यों में हालात बिगड़े

चित्रकूट में घरों में 5 फीट तक कीचड़ : यूपी के वॉटरफॉल में फंसे पर्यटकों का किया गया रेस्क्यू

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इसका असर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में भी दिखाई दे रहा है।

वेब वार्ता, नई दिल्ली

मंदाकिनी नदी के उफान के कारण रामघाट पर बना पुल नदी में समा गया, जबकि कई घरों में करीब 5 फीट तक कीचड़ भर गया है। वहीं, उत्तर प्रदेश में वॉटरफॉल में फंसे पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया है।

मंदाकिनी का जलस्तर अब कम होने लगा है, लेकिन बाढ़ के बाद कीचड़ और मलबे ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सतना में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के 58 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रयागराज और वाराणसी समेत 18 जिलों में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रशासन बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

बिहार में बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद बढ़ी मुश्किल

नेपाल में बाढ़ के बाद कोसी बैराज और गंडक बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बिहार के कई गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। भागलपुर के सबौर में गंगा के कटाव के चलते 8 घर नदी में समा गए। प्रभावित इलाकों में लोगों के सामने सुरक्षित स्थानों पर जाने की चुनौती बनी हुई है।

बिहार के 11 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में पटना, सुपौल, जमुई और रोहतास में तेज बारिश हुई। सुपौल में कोसी नदी के किनारे करीब 6 फीट लंबा मगरमच्छ मिलने से भी लोगों में दहशत फैल गई।

पंजाब-चंडीगढ़ में उमस, हल्की बारिश की संभावना

पंजाब के 12 जिलों में बारिश की संभावना है। हालांकि, कई इलाकों में लोगों को गर्मी और उमस से राहत नहीं मिली है। चंडीगढ़ में सोमवार को आसमान में हल्के बादल छाए रहने और एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। शहर के अधिकतम तापमान में करीब 0.4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है।

हिमाचल में बारिश का यलो अलर्ट, 103 लोगों की मौत

हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह तक कमजोर रहने के बाद मानसून ने फिर जोर पकड़ा है। कांगड़ा में बीती रात भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने सोमवार को कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में 31 अगस्त से 3 सितंबर तक कई जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है। 30 जून से शुरू हुए मानसून सीजन के दौरान हिमाचल प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 103 लोगों की मौत हो चुकी है।

गंगा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार थार पलटी, चार युवकों की मौत, एक किशोर घायल

हापुड़। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में गंगा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार थार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे चार युवकों की मौत हो गई। वहीं एक किशोर गंभीर रूप से घायल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया।

जानकारी के मुताबिक हादसा रविवार-सोमवार की मध्य रात्रि गंगा एक्सप्रेस-वे पर हुआ। बदायूं से दिल्ली की तरफ जा रही तेज रफ्तार थार अचानक पलट गई। थार में पांच लोग सवार थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पांचों घायल युवकों को सीएचसी में भर्ती कराया। यहां डॉक्टर ने चार युवकों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान बदायूं निवासी जोगिंदर, सुखबीर, जसवंत और रवि के रूप में हुई है। वहीं 17 साल के घायल किशोर का इलाज चल रहा है। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस ने दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुई गाड़ी को गंगा एक्सप्रेस-वे से हटाकर यातायात बहाल कराया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक थार की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। अचानक वाहन डगमगाया और देखते ही देखते बेकाबू होकर पलट गया। थार करीब 5-6 बार पलटी खाकर सड़क किनारे जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार युवक अंदर ही फंस गए।

वहीं एक अन्य हादसा ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर रविवार रात हुआ जहां कार सवार चार लोगों की मौत हो गई। हादसा जेवर थाना क्षेत्र में हुआ, जहां नोएडा से आगरा की ओर जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर और रेलिंग को तोड़ते हुए सामने से आ रही कार से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार चारों लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद जेवर थाना पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के बाद एक्सप्रेसवे पर यातायात व्यवस्था को सामान्य कर दिया गया है। पुलिस हादसे में मृत लोगों की पहचान और दुर्घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी जुटा रही है।

पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बताने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा स्पष्ट रूप से बताने और इसे पेट्रोल पंप की रसीद पर अनिवार्य रूप से दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता एनके गोस्वामी को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित हाईकोर्ट का रुख करने की स्वतंत्रता दी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार है कि वे जिस पेट्रोल की खरीदारी कर रहे हैं, उसमें इथेनॉल की मात्रा कितनी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पेट्रोल की रसीद पर इथेनॉल ब्लेंडिंग की जानकारी स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं होती। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार से इस संबंध में स्पष्ट व्यवस्था और उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की।

सुनवाई के दौरान भारत के अटॉर्नी जनरल ने याचिका को आगे बढ़ाने के तरीके पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता चाहते हैं कि केंद्र सरकार सीधे उनके प्रति जवाबदेह हो। इस पर गोस्वामी ने कहा कि उनकी मांग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि आम उपभोक्ताओं के अधिकारों से जुड़ी है। अटॉर्नी जनरल ने याचिका को प्रॉक्सी याचिका बताते हुए अदालत को यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट पिछले वर्ष इसी तरह की एक याचिका खारिज कर चुका है। इसके बाद पीठ ने मामले पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की छूट दे दी।

याचिका में की गई थीं कई मांगें

याचिका में सभी पेट्रोल पंपों के नोजल पर पेट्रोल में इथेनॉल का सटीक प्रतिशत प्रमुखता से प्रदर्शित करने और प्रत्येक बिल या रसीद पर इसकी जानकारी दर्ज करने की मांग की गई थी। इसके अलावा वाहन के निमार्ता, मॉडल, इंजन और निर्माण वर्ष के आधार पर उपयुक्त इथेनॉल मिश्रण की जानकारी देने वाला सार्वजनिक डेटाबेस बनाने की मांग भी की गई थी। पुराने या इथेनॉल-अनुकूल नहीं माने जाने वाले वाहनों के लिए कम इथेनॉल मिश्रण वाला पेट्रोल उपलब्ध कराने की नीति बनाने का सुझाव दिया गया था।

ब्रिक्स समिट से पहले दिल्ली में होगा मेगा ट्रेड फेयर, मोदी-पुतिन होंगे शामिल!

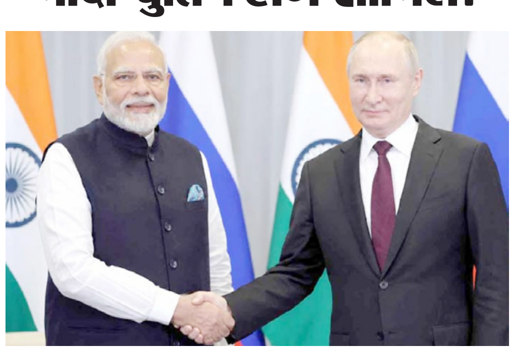

वेब वार्ता, नई दिल्ली। 18वें ब्रिक्स समिट से पहले दिल्ली में 9 से 11 सितंबर के बीच पहला बड़ा भारत-रूस इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल ट्रेड फेयर आयोजित होने जा रहा है। इस प्रदर्शनी में पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पहुंचने की उम्मीद है। इसकी जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि इस प्रदर्शनी से दोनों देशों के बीच सीधे व्यापारिक जुड़ाव, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और संयुक्त औद्योगिक प्रोजेक्ट्स के विकास के लिए नए अवसर मिलने की उम्मीद है। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए भारत आएंगे।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत-रूस संबंधों के जानकारों का कहना है कि मोदी और पुतिन का इस प्रदर्शनी का दौरा यह दिखाता है कि दोनों देशों के बीच औद्योगिक और आर्थिक सहयोग को कितना महत्व दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम से जुड़े लोगों ने बताया कि प्रदर्शनी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रसायन, डिजिटल तकनीक, खनन एवं उत्खनन तकनीक, मानव-केंद्रित तकनीक और द्विपक्षीय व्यापार एवं औद्योगिक सहयोग जैसे क्षेत्रों पर फोकस रहेगा। जानकारी के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स समिट की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली का दौरा कर सकते हैं। पुतिन का नई दिल्ली दौरा एक साल में दूसरी बार है। वहीं भारत ने इस साल 13 जनवरी 2026 को ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता संभाली थी। 14 जनवरी के आसपास भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस समिट से जुड़े आधिकारिक थीम, लोगो और वेबसाइट का शुभारंभ किया था। इससे पहले पुतिन दिसंबर 2025 में दो दिवसीय दौरे पर भारत आए थे, जहां उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की और 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे।

आईएनएस निपुण भारतीय नौसेना में शामिल

वेब वार्ता, मुंबई। मुंबई में भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में अत्याधुनिक पोत आईएनएस निपुण को शामिल किया है। इस मौके पर नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा कि हम एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ समुद्री क्षेत्र तेजी से प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है। उन्होंने बताया कि खतरों को लेकर धारणा लगातार बदल रही है और वे नई चुनौतियों तथा जटिलताओं के रूप में सामने आ रही हैं।

समुद्र में 300 मीटर की गहराई तक जाने की क्षमता रखने वाला यह जहाज पनडुब्बियों को तुरंत राहत प्रदान करने में सक्षम है। इसके अलावा, आईएनएस निपुण को आपदा राहत और मानवीय सहायता अभियानों के लिए भी तैनात किया जा सकता है, जो इसकी बहुमुखी प्रतिभा को दिखाता है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों, विशेषकर पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच, यह रणनीतिक बदलाव और भी महत्वपूर्ण होता है।

उन्होंने कहा कि उस समय में जब समुद्री क्षेत्र लगातार अधिक प्रतिस्पर्धी और चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, आईएनएस निपुण का शामिल होना नौसेना की क्षमताओं को मजबूत करेगा और उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा।

जबलपुर एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग में टपका पानी

वेब वार्ता, जबलपुर। डुमना एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग में बारिश के दौरान पानी टपकने का मामला सामने आया है। मुख्य प्रवेश द्वार के पास कैनोपी से पानी गिरने के कारण फर्श गीला हो गया और फिसलन की स्थिति बन गई। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन ने मुख्य गेट बंद कर दूसरे गेट से आवाजाही कराई।

फर्श गीला हुआ तो लगाया चेतावनी बोर्ड

पानी के कारण यात्रियों के फिसलने की आशंका को देखते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन ने मुख्य गेट के पास

'सावधान! फर्श गीला है, कृपया संभलकर चलें' लिखा बोर्ड लगाया। यात्रियों को दूसरे गेट से टर्मिनल में प्रवेश कराया गया। एयरपोर्ट प्रभारी डायरेक्टर नीरज कुमार के मुताबिक, बारिश के कारण कैनोपी में पानी भर गया था। कैनोपी की रिपेयरिंग का काम चल रहा है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए ऊ1 गेट बंद कर ऊ2 गेट से आवाजाही कराई गई।

2024 में भी गिर चुकी है कैनोपी

डुमना एयरपोर्ट पर कैनोपी को लेकर पहले भी समस्या सामने आ चुकी है। जून 2024 में तेज बारिश के दौरान ड्रॉप एंड गो एरिया की फैब्रिक कैनोपी का एक हिस्सा पानी जमा होने के बाद टूटकर नीचे खड़ी कार पर गिर गया था। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ था, लेकिन कार क्षतिग्रस्त हो गई थी।

450 करोड़ की परियोजना पर फिर उठे सवाल

करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नई टर्मिनल बिल्डिंग के उद्घाटन के कुछ समय बाद ही कैनोपी की घटना सामने आई थी। अब बारिश में पानी टपकने की समस्या सामने आने के बाद एयरपोर्ट की व्यवस्थाओं को लेकर फिर सवाल उठ रहे हैं। वायु सेवा संघर्ष समिति ने एयरपोर्ट के निर्माण और मौजूदा व्यवस्थाओं की उच्चस्तरीय जांच और तकनीकी ऑडिट की मांग की है। फिलहाल कैनोपी की मरम्मत का काम चल रहा है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए वैकल्पिक गेट से आवाजाही की व्यवस्था की है।

नेपाल की बाढ़ अब तक 788 की मौत, सुरंगों में फंसे लोगों की तलाश जारी

नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव दल हाइड्रोपावर सुरंगों में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं।

वेब वार्ता, काठमांडु

अधिकारियों के मुताबिक 788 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि अब भी 2500 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में शव मिलने के कारण प्रशासन को उन्हें सुरक्षित रखना भी मुश्किल हो रहा है। फ्रीजर की कमी के चलते करीब 200 अज्ञात शवों को दफनाना पड़ा। तिब्बत में ग्लेशियर टूटने के चलते तो लैंडस्लाइड आया था, उसकी वजह से चीन में भी कम से कम 16 लोगों की मौत हुई है, जबकि दोनों देशों में करीब 3000 लोग लापता हैं।

...याद कर रहे हैं

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में आई भयानक बाढ़ के बाद अब तक कुल 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। सभी 149 भारतीय नागरिकों की लिस्ट एक्स पर पोस्ट की। इस बीच भारत से लगातार राहत सामग्री नेपाल भेजी जा रही है। बाढ़ के बीच कई दिल दहला देने वाली घटनाएं भी सामने आई हैं। तबाह गांवों में लोग लौटकर अपने घरों और परिवारों को याद कर रहे हैं। एक स्कूल के छात्र सिर्फ दोपहर का खाना खाने के लिए कक्षा से बाहर गए थे, जिससे वे बड़े हादसे की चपेट में आने से बच गए।

सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड के दो शूटर एनकाउंटर में ढेर, 20 राउंड चली गोलियां

वेब वार्ता, शामली। हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में यूपी पुलिस ने सोमवार सुबह बड़ी कार्रवाई की। पुलिस मुठभेड़ में हत्याकांड के दो कथित शूटर सुमित और मोहित मारे गए। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से करीब 20 राउंड फायरिंग हुई।

शामली एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी बाइक से शामली से सोनीपत की ओर भाग रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने दोनों को घेर लिया। पुलिस के मुताबिक, पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं। मुठभेड़ में सुमित (24) और

मोहित (22) को गोली लगी। पुलिस दोनों को जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

दोनों पर कई आपराधिक मामले दर्ज

पुलिस के अनुसार, सुमित और मोहित सोनीपत के रहने वाले थे। सुमित के खिलाफ एक जबकि मोहित के खिलाफ 15 आपराधिक मामले दर्ज बताए गए हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर सिंगर अंकित बालियान की हत्या को अंजाम दिया था। मामले में आरोपी सत्यम और आर्यन अभी फरार हैं। 26 अगस्त की शाम 32 वर्षीय अंकित बालियान शामली में जिम करके बाहर निकले थे। इसी दौरान हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और करीब 18 राउंड फायरिंग की। गोली लगने से अंकित गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सिंगर को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की थी। अब दो कथित शूटरों के मारे जाने के बाद पुलिस फरार सत्यम और आर्यन की तलाश में जुटी है।

संपादकीय

सोलन को मिला ताज

सोलन कैश क्रॉप के अलावा पर्यटन और खास तौर पर हाई वे टूरिज्म में अव्वल साबित हुआ है। जाहिर तौर पर शिक्षा के हब बनते सोलन ने मानव संसाधन विकास में श्रेष्ठता व दक्षता हासिल की है, जबकि स्वरोजगार व व्यापार की दृष्टि में जिला ने शहरी विकास का महत्त्व रेखांकित किया है। जिला में प्रति व्यक्ति आय 8.10 लाख रुपए आंकी गई है जो राष्ट्रीय औसत से कहीं आगे है। आर्थिक कत्तव्य पथ पर खड़े सोलन ने अपनी उपलब्धियों से पूरे प्रदेश को भी सींचा है, क्योंकि रोजगार के लिहाज से बीबीएन में करीब चार लाख लोगों को अवसर मिल रहे हैं। ऐसे में जबकि सोलन जिला के माध्यम से हिमाचल के आर्थिक संबोधन तय हो रहे हैं, यह जरूरी है कि हम विकास के इस पथ को और चौड़ा करें। हम पहले भी कहते रहे हैं और अब पुनः दोहरा देते हैं कि बीबीएन को प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में दर्जा व महत्त्व मिलना चाहिए। इसके लिए वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालय यहां शिफ्ट होने चाहिएं तथा औद्योगिक संगठन व कार्यालयों का संचालन भी यहीं से होना चाहिए। सोलन जिला ने आर्थिक मुकुट पहनकर प्रदेश के बाकी जिलों को भी तरक्की, विकास और आगे बढ़ने का आगाज सौंपा है।

राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण में हिमाचल के जिला सोलन का देश के टॉप पांच जिलों में शरीक होना एक उपलब्धि है और यह संकेत भी कि प्रदेश की आर्थिकी कैसे आगे बढ़ सकती है। चंडीगढ़ से समीपता के कारण सोलन जिला ने बहुआयामी तरक्की की है, खास तौर पर बीबीएन क्षेत्र का औद्योगिक विकास उल्लेखनीय तरक्की का कारण बना है।

प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों पर औद्योगिक गलियारा विकसित किया जाए, तो बाकी जिला भी आर्थिक नक्शे पर खुशहाल होंगे। कभी पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वाई एस परमार ने काला अंब, परवाणू, नालागढ़, मैहतपुर से संसारपुर टैरस तक एक औद्योगिक पट्टी विकसित की थी। आज इसकी रूपरेखा बढ़ाते हुए सारे सीमांत क्षेत्र को औद्योगिक गलियारा बना देना चाहिए। इसी तरह हिमाचल के मध्यम भाग में शिक्षा के हब, कृषि-बागबानी तथा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पर्यटन को तवज्जो दें, तो आर्थिक ढांचा और सुदृढ़ होगा। प्रदेश की ग्रामीण आर्थिकी को संबल देने के लिए जैव खेती का प्रचलन कारगर साबित हुआ है, जबकि वर्तमान सुक्खू सरकार ने मक्की व हल्दी के समर्थन मूल्य बढ़ा कर किसान की आय को प्रोत्साहित किया। इसी तरह दुग्ध उत्पादन की खरीद दरें बढ़ा कर सरकार ने डेयरी क्षेत्र को आशाजनक बना दिया है। सारे हिमाचल को सोलन की तर्ज पर समृद्ध बनाने की चुनौती पर कनेक्टिविटी से काफी मदद मिलेगी। फोरलेन परियोजनाओं के अलावा कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार योजना से क्षेत्रीय आर्थिकी का विस्तार होगा। कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने के सारे उद्देश्य पूरे हो जाएं, तो निश्चित रूप से जिला में प्रति व्यक्ति आय का विस्तार होगा। प्रदेश में रोजगार के साधन बढ़ाने के हर प्रयास से प्रति व्यक्ति आय में विस्तार होगा। प्रदेश में उद्योगों के अलावा अगर आईटी पार्क, ट्रांसपोर्ट नगर तथा फिल्म सिटी जैसी परियोजनाओं पर काम करें तो निश्चित रूप से जीडीपी में बढ़ोतरी के साथ-साथ प्रति व्यक्ति आय व व्यय में भी वृद्धि होगी।

महंगाई नियंत्रण की कारगर रणनीति जरूरी

प्याज, टमाटर और आलू की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए नाफेड जैसे सरकारी संगठनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर सीधी बिक्री बढ़ाई जानी होगी। आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी रोकने के लिए व्यापारियों के स्टॉक सीमाओं की सख्त निगरानी आवश्यक होगी।

इन दिनों महंगाई पर प्रकाशित हो रही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में भारत में महंगाई बढ़ने से आम आदमी के जीवन की मुश्किलें बढ़ने संबंधी चिंताएं प्रस्तुत की जा रही हैं। हाल ही में 27 अगस्त को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एस एंड पी ग्लोबल ने मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण ऊंची ऊर्जा कीमतों और अल नीनो से प्रभावित कमजोर मानसून की चुनौतियों की वजह से चालू वित्त वर्ष 2026-27 में भारत में खुदरा महंगाई (सीपीआई) के बढकर 5.1 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान जताया है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति सहित प्रमुख आर्थिक एजेंसियों ने भारत में खुदरा महंगाई बढ़ने की चेतावनी दी है। एचडीएफसी बैंक ने सितंबर से खुदरा महंगाई दर लगातार 5 प्रतिशत से ऊपर रहने का अनुमान लगाया है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स व जेपी मॉर्गन ने खाद्य और कच्चे तेल की बढ़ती लागत के कारण महंगाई में और वृद्धि की चिंता जाहिर की है। एसबीआई इकोरैप रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जो खुदरा महंगाई अगस्त में 4.7 प्रतिशत अनुमानित है, वह अक्टूबर-नवंबर में 6 प्रतिशत के पार पहुंच सकती है। ऐसे में सरकार के द्वारा महंगाई नियंत्रण के और अधिक कारगर रणनीतिक कदम जरूरी दिखाई दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2026 में भारतीय बाजार में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भारी उछाल दर्ज किया गया है। मौसम की अनिश्चितता और फसल प्रभावित होने से चीनी के खुदरा भाव ऊंचाई पर पहुंच गए हैं।

सीमित आपूर्ति के कारण प्याज के दाम पिछले साल की तुलना में तेजी से बढ़े हैं। इसके अलावा सरसों तेल, रिफाइंड तेल और दालों के दाम भी ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। त्योहारों के मौसम में मांग बढ़ने, चारे की लागत और परिवहन खर्च में वृद्धि के कारण दूध, मिठाइयों, पैकबंद खाद्य पदार्थों और पैक्ड चाय की कीमतों में और बढ़ोतरी होने की आशंका जताई जा रही है। यह परिदृश्य स्पष्ट संकेत देता है कि कमजोर मानसून और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें आने वाले महीनों में आम नागरिक के बजट पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में जुलाई महीने में खुदरा महंगाई दर बढकर 4.45 प्रतिशत हो गई है, जो जून में 4.38 प्रतिशत थी। यह आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 4 प्रतिशत के तय लक्ष्य से ऊपर बना हुआ है। महंगाई में इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें हैं। निश्चित रूप से खाद्य वस्तुओं की बढ़ती महंगाई के कारण आम आदमी की थाली महंगी हो गई है। जीवन निर्वाह लागत बढ़ गई है। क्रिसिल की अगस्त 2026 की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2026 में घर पर बनने वाली शाकाहारी थाली की औसत लागत सालाना आधार पर 4 प्रतिशत बढकर 29.1 रुपए हो गई। यह पिछले 7 महीनों का उच्चतम स्तर है। वहीं, मांसाहारी थाली की कीमत 9 प्रतिशत बढकर 58.3 रुपए पर पहुंच गई। थाली महंगी होने का मुख्य कारण प्याज, खाद्य तेल और रसोई गैस की दरों में वृद्धि है। इस परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद देश में महंगाई, आर्थिक स्थिति और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि से जुड़ी तस्वीर पेश करते हुए कहा कि वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल और कमजोर मानसून की चुनौतियों के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.0 प्रतिशत कर दिया है। जहां खाद्य वस्तुओं के क्षेत्र में महंगाई में कुछ वृद्धि के संकेत हैं, वहीं अन्य क्षेत्रों में महंगाई बढ़ने के संकेत नहीं हैं। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में मानसून, अल नीनो और पश्चिम एशिया के संघर्ष की वजह से खाने-पीने की वस्तुएं और ईंधन महंगे हो सकते हैं। निःसंदेह अब ऊंची ऊर्जा लागत, अल नीनो और कमजोर मानसून के कारण महंगाई की चिंता बढ़ती जा रही है।

इससे कृषि पर मंडराता खतरा भी दिखाई दे रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जून-सितंबर के बीच देश में सामान्य वर्षा के मुकाबले लगभग 15 प्रतिशत की कमी अनुमानित की गई है। इस स्थिति के पीछे अल-नीनो प्रभाव को मुख्य कारण माना जा रहा है, जिसने मानसून की गति को धीमा कर दिया है। शुरूआत में कम बारिश और मिट्टी में नमी की कमी के कारण इस वर्ष खरीफ फसलों की बुआई का कुल रकबा प्रभावित हुआ है। विशेष रूप से धान, सोयाबीन और दलहन जैसी फसलों का बुआई क्षेत्र पिछले साल की तुलना में सिकुड़ गया है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं हैं, वहां फसलों के सूखने का जोखिम काफी बढ़ गया है। बारिश की लगातार कमी से मिट्टी में नमी का स्तर घट रहा है। इससे न केवल कुल खाद्यान्न उत्पादन घट सकता है, बल्कि किसानों की आय प्रभावित होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल दबाव पड़ सकता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा जुलाई की शुरूआत से लेकर अब तक महंगाई नियंत्रण के लिए बहुआयामी रणनीतिक कदम उठाए गए हैं। हाल ही में खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण खुदरा मुद्रास्फीति में तेजी के कारण आर्थिक दबाव से आम जनता को राहत देने और बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यावहारिक रणनीतियां अपनाई हैं। खाद्य पदार्थों और ईंधन के दामों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं के राष्ट्रीय बफर स्टॉक का उपयोग किया जा रहा है। बाजार में शक्कर, प्याज और अन्य कृषि उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाकर कीमतों को थामने का सीधा प्रयास किया जा रहा है। कांदा एक्सप्रेस की उपयोगिता दिखाई दे रही है।

वित्तीय बाजार में नकदी के संतुलन को बनाए रखने और अत्यधिक मांग से मूल्य वृद्धि रोकने के लिए केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक समीक्षा के तहत नकदी प्रवाह पर सख्त नियंत्रण रखा है। दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रगति और फसलों की बुआई की लगातार समीक्षा की जा रही है, ताकि आने वाले समय में खाद्यान्न की कमी न हो और कीमतों में उछाल को रोका जा सके। वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों से ईंधन और आयातित वस्तुओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए व्यापारिक रणनीतियों में आवश्यक बदलाव किए गए हैं। संभावित मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए आवश्यक उपभोग योग्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का खाका तैयार किया गया है। इन सब के साथ-साथ सरकार आगामी महीनों में अल नीनो तथा कमजोर मानसून की चुनौतियों से निपटने के लिए भी सावधानी और सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ रही है। उम्मीद करें कि सरकार महंगाई नियंत्रण के लिए और अधिक नए रणनीतिक कदमों के साथ आगे बढ़ेगी। सरकारी गोदामों से गेहूं, चावल और दालों को उपयुक्त रूप से खुले बाजार में जारी किया जाना होगा, ताकि आगामी त्योहारी सीजन में आपूर्ति बनी रहे। प्याज, टमाटर और आलू की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए नाफेड जैसे सरकारी संगठनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर सीधी बिक्री बढ़ाई जानी होगी। आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी रोकने के लिए व्यापारियों के स्टॉक सीमाओं की सख्त निगरानी आवश्यक होगी। खाद्य तेलों और दालों की उपलब्धता सुधारने हेतु आयात शुल्क में अस्थायी कटौती की जानी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति को ज्यादा असरदार बनाते हुए बाजार से तरलता सोखने हेतु उपयुक्त रूप से ब्याज दर बढ़ाई जानी होगी। महंगाई में पिस रहे गरीब लोगों को राहत देनी होगी।

डा. जयंती लाल भंडारी
विख्यात अर्थशास्त्री

हिंदू राष्ट्र का मतलब, मुसलमानों के बिना नहीं

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने शनिवार को वन वर्ल्ड वन ह्यूमैनिटी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जो कहा है, उसकी विश्व भर में चर्चा हो रही है। विशेष रूप से भारत में उनके बयान पर बड़ी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रहीं हैं। मोहन भागवत ने न्यूयार्क में विचार व्यक्त करते हुए कहा, मानवता की एकता, भारत का पारंपरिक विचार है। हमारे नेताओं ने संविधान पर जोर दिया है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, भारत की राजनीति स्वार्थ आधारित हो गई है। जहां मैं और मेरा है वहां समाधान नहीं मिल रहा है। भागवत बोले सामाजिक धार्मिक संगठन राजनीति और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करना चाहें, तो लोकतंत्र में जनमत से ही सरकार चलती है। हमें मजबूत जनमत तैयार करना होगा, जो राजनीति को प्रभावित करे। उन्होंने कहा सारे रास्ते ईश्वर तक ले जाते हैं। मानव जीवन की अपनी गरिमा है। मनुष्य जीवन में किसी भी आधार पर कोई भेद नहीं किया जा सकता है। जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उस समय कोई हिंदू यह नहीं सोचता है, कि भारत में मुस्लिम नहीं होने चाहिए। पूरी मानवता एक है। विविधता हमारी आंतरिक एकता को मजबूत करती है। हमें उसको स्वीकार करते हुए सभी का सम्मान करना चाहिए। मोहन भागवत ने जो कहा है, उससे किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता है। पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से भारत में मुसलमान और ईसाइयों को लेकर 80:20 का जो विवाद पैदा किया गया है, भारत में जिस तरह से धार्मिक एवं जाति समीकरण की दिशा में राजनीति बढ़ती चली जा रही है।

मुसलमानों और ईसाइयों को एक विचारधारा के लोगों द्वारा तरह-तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, वह दोयम दर्जे के नागरिक बनकर रहें। खाना-पीना, शिक्षा और धार्मिक क्रियाकलाप हिंदुओं द्वारा तय किए जा रहे है। अन्य धर्म एवं जाति आधार उन्हीं का पालन करने का दबाव सरकारी संरक्षण में बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उन्होंने अमेरिका में जो कहा है, वह अलग है भारत में जो हो रहा है, वह अलग है। मोहन भागवत के विदेश प्रवास के पहले ही अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा एवं अन्य स्थानों पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली है। मोहन भागवत के वीजा को रद्द करने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने जैसी मांग अमेरिका में बड़ी तेजी के साथ उभरी है। जिसके कारण मोहन भागवत का यह दौरा विवादों से घिरा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख, समय-समय पर जो कहते हैं, उस पर वह ज्यादा समय तक स्थिर नहीं रहते हैं। हाल ही में जब वह अमेरिका के दौर में गए वहां पर उनके उद्योगपतियों से भेंट के कार्यक्रम को गुप्त रखा गया। भारत में निवेश करने के लिए उद्योगपतियों को जो कठिनाइयां हो रही हैं उस पर उन्होंने चर्चा की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के स्वयंसेवक रह चुके हैं। भारत और सारी दुनिया के देशों में यह माना जाता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सलाह पर ही वर्तमान सरकार पिछले 12 वर्षों से काम कर रही है। ऐसी स्थिति में मोहन भागवत के इस बयान को अमेरिका में गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। विश्व के कई देशों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सैकड़ो अनुवांशिक संगठन है। जो अलग-अलग तरीके से अपनी बात करते हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं है, जिसके बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके अनुवांशिक संगठन तरह-तरह से हस्तक्षेप करके संबधित वर्ग को अपने पक्ष में लाने का प्रयास न करते हों। वह जो कहते हैं, वह करते नहीं है। कुल मिलाकर हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर एक कट्टर संगठन के रूप में भारत और दुनिया के देशों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहचान बनी है। विदेश में एक कट्टरवादी संगठन के रूप में संघ को पहचान मिली है।

भारत में ईसाई और मुस्लिमो के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, उसकी चर्चा पिछले एक दशक से दुनिया के देशों में हो रही है। इस छवि को मिटा पाना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके अनुवांशिक संगठनों के लिए बहुत आसान नही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार आयोग संगठन एवं अन्य धार्मिक संगठन यह मानकर चलते हैं, भारत में मानव अधिकारों का उल्लंघन अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हो रहा है। इसमें भारत सरकार की भी सहमति है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की कथनी और करनी में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह विदेश दौरा संघ और वर्तमान सरकार के हितों का संवर्धन किस तरह से कर पाएगा? इसको लेकर चचाएं हो रही हैं। जिस तरह के राजनीतिक संकट से भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सामना कर रही है, उससे निपटने के लिए, अब संघ ने स्वयं कमान संभाली है। मोहन भागवत के इस दौरे को इसी रूप में देखा जा रहा है। यह कितना सफल होगा, इसका पता तो भविष्य में ही लगेगा। जिस तरह से अमेरिका और यूरोप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके अनुवांशिक संगठनों के खिलाफ वातावरण देखने को मिल रहा है, वह संघ और भारत सरकार के लिए चिंता का विषय है। जब तक कथनी और करनी में समानता नहीं होगी, तब तक यह संकट बना रहेगा।

(लेखक- सनत जैन

कचरे के ढेर, बीमारियों के शहर

हम अपने घर को साफ रखने के महत्व से अवगत हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, हमारी जिम्मेदारी की भावना गायब हो जाती है। कई लोगों को घरेलू सामान सड़क के किनारे, नाले में, खाली जगह पर या सार्वजनिक स्थानों पर फेंकने की आदत पड़ गई है। प्लास्टिक बैग, पॉलिथीन, सब्जियों के छिलके, फलों के अवशेष और बचा हुआ खाना नियमित रूप से खुले में फेंक दिया जाता है। लेकिन लापरवाही का यह मामूली सा काम धीरे-धीरे लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन रहा है।

खुले में कूड़ा फेंकने से वह सड़ने लगता है और दुर्गंध आने लगती है। समस्या केवल 'असुविधा' की नहीं है। कचरे के जमाव से गंदगी फैलती है और मक्खियाँ, मच्छर, आवारा जानवर और अन्य कीट आकर्षित होते हैं। प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थ नालियों को जाम कर सकते हैं जिससे बरसात के मौसम में पानी जमा हो जाता है। पानी के बहाव में कमी से मच्छरों के पनपने के स्थान बन जाते हैं और बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। यदि कोई एक व्यक्ति लापरवाही बरतता रहता है, तो यह पूरे मोहल्ले के लिए स्वास्थ्य समस्या बन सकता है।

सबसे बुरी बात यह है कि समाज के लोग इसे एक सामान्य बात समझने लगे हैं। हम सड़क किनारे कचरे के ढेर देखते हैं, कुछ पल के लिए नाक ढक लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बहुत कम लोग सोचते हैं कि यह कचरा कहाँ से आता है। वास्तव में, हर कचरे के पीछे किसी न किसी की सुविधा और लापरवाही होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में कभी कचरा नहीं डालता, तो वह उसे घर के बाहर कूड़ेदान में क्यों नहीं डालता? जब हम अपने घरों से दूर होते हैं तो सड़कें कूड़ेदान क्यों बन जाती हैं? यह सिर्फ स्वच्छता से कहीं बढ़कर है झ यह नागरिक कर्तव्य और सामाजिक आचरण का मामला है। प्लास्टिक और पॉलीथीन के इस्तेमाल से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्लास्टिक आसानी से नष्ट नहीं होता और लंबे समय तक पर्यावरण में बना रहता है। अगर इसे यूं ही फेंक दिया जाए, तो यह नालियों को जाम कर सकता है और पानी के बहाव को रोक सकता है। प्लास्टिक की थैलियों में बचा जैविक कचरा सड़ता रहता है और दुर्गंध फैलाता है, जिससे अस्वच्छता पैदा होती है। आवारा जानवर भी प्लास्टिक खा सकते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। इसलिए, प्लास्टिक का अंधाधुंध और लापरवाही से निपटान समाज, जानवरों और पर्यावरण को प्रदूषित करता है।

कचरे और बीमारियों के बीच संबंध में धारणा और वास्तविकता में कोई अंतर नहीं है। खुले कूड़ेदानों में मक्खियाँ और अन्य परजीवी जमा हो जाते हैं, जो बीमारियाँ फैलाते हैं। जमा हुआ और ठहरा हुआ पानी मच्छरों के प्रजनन का स्थान बन सकता है। अनियंत्रित कचरे से कम दूरी पर स्थित घरों में संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा अधिक हो सकता है। इस मानसून के मौसम में स्थिति और भी खराब हो सकती है, क्योंकि बारिश के मौसम में कचरा और दूषित पदार्थ आसपास के इलाकों में फैल सकते हैं। लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि समस्या केवल नगरपालिकाओं की है। स्थानीय सरकारें समुदाय को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं: कूड़ा संग्रहण, अपशिष्ट निपटान, नालियों का रखरखाव और सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता। साथ ही, इस प्रक्रिया में नागरिकों की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें अपशिष्ट निपटान करते समय ज़िम्मेदार होना चाहिए, कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, प्लास्टिक का अनावश्यक उपयोग सीमित करना चाहिए और गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग करना चाहिए। हालांकि, अगर निवासी सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकते रहेंगे तो अधिक सफाई कर्मचारियों की तैनाती से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। अब जरूरत इस बात की है कि स्वच्छता को सरकारी अभियान के रूप में न लिया जाए। स्वच्छता अभियानों की प्रभावशीलता स्पष्ट रूप से दैनिक जीवन में स्वच्छता को शामिल करने से जुड़ी है। बच्चों को स्कूलों में स्वच्छता पर भाषण देखने चाहिए, साथ ही उन्हें स्वच्छता बनाए रखने के लिए कई व्यावहारिक उपाय भी अपनाने चाहिए, जिनमें कचरे का पृथक्करण, कचरे का उचित निपटान और एकल-उपयोग प्लास्टिक का कम से कम उपयोग शामिल है। समुदायों में स्थानीय निगरानी प्रणाली भी विकसित की जा सकती है और निवासियों को अपने पर्यावरण के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सकता है। हालांकि नियम और दंड आवश्यक हो सकते हैं, व्यवहार में बदलाव तब तक नहीं आएगा जब तक वे जिम्मेदार आचरण के महत्व को नहीं पहचानते। सार्वजनिक क्षेत्र में स्वच्छता पर होने वाली राजनीतिक चर्चा में भी कचरे की राजनीति झलकती है। स्वच्छता और कूड़ा संग्रहण, जल निकासी और नागरिक अवसंरचना चुनाव के दौरान प्रमुख राजनीतिक मुद्दे होते हैं। हालांकि, चुनाव समाप्त होते ही ये चिंताएं आसानी से भुला दी जाती हैं। कूड़े के ढेर फिर से लग जाते हैं, नालियां जाम हो जाती हैं और दुर्गंध फिर से आम हो जाती है। "यह चक्र चलता रहता है, क्योंकि प्रशासनिक जवाबदेही अक्सर असंगत होती है और जनता की भागीदारी भी कम होती है।" यह समझना महत्वपूर्ण है कि कचरा केवल नगरपालिका की समस्या नहीं है। यह हमारी दिनचर्या, प्राथमिकताओं और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना का सूचक है। जब हम सार्वजनिक सड़क को अपने घर के आंगन की तरह ही अपनी जिम्मेदारी समझने लगेंगे, तभी हम बदलाव लाना शुरू कर पाएंगे। स्वच्छ सड़कें न केवल देखने में सुंदर लगती हैं, बल्कि एक स्वस्थ और अधिक जिम्मेदार समाज का प्रतीक भी हैं। बीमार होने पर लोगों को अस्पताल और दवाइयों की जरूरत पड़ती है, लेकिन बेहतर यही है कि हानिकारक स्थितियों से पहले ही बचा जाए। कचरे की समस्या यह है कि हमें यह समझना होगा कि यह आपकी समस्या नहीं है। स्वच्छता का रहस्य किसी बड़े ऐलान या सरकारी अभियान में नहीं, बल्कि एक छोटे से व्यक्तिगत निर्णय में है: सड़क पर कूड़ा न डालें - उसे कूड़ेदान में डालें। इस छोटी सी आदत को बदलकर हम इन मोहल्लों को, अपने शहरों को और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। स्वच्छता की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं है; यह किसी एक विभाग, किसी एक सरकार या कर्मचारियों के समूह की जिम्मेदारी नहीं है। यह हम सबकी जिम्मेदारी है और इसकी शुरूआत हममें से प्रत्येक से होनी चाहिए।

डॉ. प्रियंका सौरभ

आलेख

दुनिया के लिए चिंता का विषय बना अलनीनो

धरती का बदलता मिजाज अब केवल वैज्ञानिकों के शोध और मौसम विशेषज्ञों की रिपोर्ट तक सीमित विषय नहीं रह गया है। इसका असर आम आदमी के जीवन से लेकर कृषि, जल संसाधन, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य तक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। कहीं आसमान से बरसती आग लोगों को बेहाल कर रही है, तो कहीं कुछ ही घंटों में होने वाली मूसलाधार बारिश शहरों को जलमग्न कर रही है। कहीं किसान बारिश का इंतजार करते-करते परेशान हैं, तो कहीं अत्यधिक वर्षा उनकी महीनों की मेहनत को बहा ले जा रही है। मौसम के इस बदलते और असामान्य स्वरूप के बीच अल नीनो एक बार फिर दुनिया के लिए चिंता का विषय बनकर सामने आता है।

अल नीनो प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से में समुद्री सतह के तापमान के सामान्य से अधिक गर्म होने से जुड़ी एक प्राकृतिक जलवायु घटना है। इसका प्रभाव केवल प्रशांत महासागर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान, वर्षा और हवाओं के पैटर्न को प्रभावित कर सकता है। यह घटना प्राकृतिक जलवायु चक्र का हिस्सा है और हजारों वर्षों से पृथ्वी की जलवायु व्यवस्था में इसका अस्तित्व रहा है। लेकिन आज परिस्थितियां पहले जैसी नहीं हैं। मानव गतिविधियों के कारण पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अल नीनो और बढ़ते वैश्विक तापमान का मेल मौसम की चरम स्थितियों को और अधिक गंभीर बना सकता है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अल नीनो को लेकर इतनी चिंता क्यों है? इसका उत्तर इसके व्यापक प्रभावों में छिपा है। अल नीनो के दौरान दुनिया के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक बढ़ सकता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में वर्षा के स्वरूप में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए यह स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। देश की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है और आज भी खेती का एक बड़ा हिस्सा मानसूनी बारिश पर आधारित है। यदि बारिश सामान्य से कम होती है या उसका वितरण असमान रहता है, तो इसका सीधा असर खरीफ फसलों पर पड़ सकता है।

धान, मक्का, दालें, तिलहन और अन्य फसलों की पैदावार प्रभावित होने का खतरा बढ़ जाता है। उत्पादन में कमी का असर केवल किसान तक सीमित नहीं रहता। इससे खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं और महंगाई पर दबाव पैदा हो सकता है। पहले से ही महंगाई और रोजगार जैसी चुनौतियों से जूझ रहे आम परिवारों के लिए खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी अतिरिक्त बोझ बन सकती है।

लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी कम गंभीर नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण जब वातावरण अधिक गर्म होता है, तो उसमें नमी धारण करने की क्षमता बढ़ती है। परिणामस्वरूप कई बार कम समय में अत्यधिक बारिश होने लगती है। ऐसी बारिश सामान्य मानसून से अलग होती है। कुछ घंटों में इतनी वर्षा हो जाती है कि शहरों की जल निकासी व्यवस्था जवाब दे देती है, नदियां उफान पर आ जाती हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। यानी एक ओर सूखे जैसी स्थिति और दूसरी ओर अचानक बाढ़—दोनों परिस्थितियां एक ही बदलती जलवायु व्यवस्था का हिस्सा बन सकती हैं।

भारत के लिए यह खतरा इसलिए भी गंभीर है क्योंकि देश की भौगोलिक विविधता बहुत अधिक है। हिमालयी क्षेत्र में भारी बारिश और बादल फटने जैसी घटनाएं जान-माल को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मैदानी इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। वहीं महानगरों में कुछ घंटों की तेज बारिश ही यातायात, बिजली, सीवर और जनजीवन को अस्त-व्यस्त करने के लिए पर्याप्त है। ऐसे में यह समझना होगा कि केवल बारिश की कुल मात्रा देखना पर्याप्त नहीं है; बारिश कब, कितनी तेजी से और किस क्षेत्र में होती है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

अल नीनो का असर समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी पर भी पड़ सकता है। समुद्र का तापमान बढ़ने से समुद्री जीव-जंतुओं और मछली उत्पादन पर असर पड़ सकता है। समुद्र दुनिया की जलवायु प्रणाली का महत्वपूर्ण नियामक है। इसलिए समुद्र के तापमान में होने वाला बदलाव लंबे समय तक वातावरण और मौसम को प्रभावित कर सकता है। यदि समुद्रों का तापमान लगातार बढ़ता रहा तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव और बढ़ेगा।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बदलता मौसम बड़ी चुनौती बन रहा है। अत्यधिक गर्मी से हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। कमजोर वर्ग, बुजुर्ग, बच्चे और खुले में काम करने वाले श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। दूसरी ओर बाढ़ के बाद जलजनित बीमारियों और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन और अल नीनो का प्रभाव केवल मौसम विभाग के आंकड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का भी विषय है।

अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कृषि उत्पादन में कमी, बिजली की मांग में वृद्धि, जल संकट, बाढ़ से बुनियादी ढांचे को नुकसान और स्वास्थ्य संबंधी खर्च—इन सभी का आर्थिक बोझ सरकार और जनता दोनों को उठाना पड़ता है। अत्यधिक गर्मी में बिजली की मांग बढ़ती है, जबकि जल संकट से उद्योग और कृषि दोनों प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी ओर बाढ़ और भूस्खलन से सड़कों, पुलों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है।ऐसे समय में सरकारों की जिम्मेदारी केवल राहत और मुआवजे तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि जलवायु जोखिम को विकास की हर योजना का हिस्सा बनाया जाए। शहरों की जल निकासी व्यवस्था को आधुनिक बनाया जाए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण हो, जल संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए और किसानों को मौसम आधारित कृषि सलाह समय पर उपलब्ध कराई जाए। सूखा और बाढ़ दोनों से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर अलग-अलग रणनीतियां तैयार करनी होंगी।

कृषि क्षेत्र में भी पारंपरिक सोच से आगे बढ़ने की जरूरत है। कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली फसलों, सूखा और गर्मी सहन करने वाली किस्मों, माइक्रो-इरिगेशन तथा वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना होगा। किसानों को मौसम की वास्तविक समय की जानकारी और संभावित जोखिमों के बारे में पहले से चेतावनी मिलनी चाहिए। इससे वे बुवाई, सिंचाई और कटाई से जुड़े निर्णय अधिक वैज्ञानिक ढंग से ले सकेंगे।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अल नीनो को केवल एक अस्थायी प्राकृतिक घटना मानकर उसके खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अल नीनो आएगा और जाएगा, लेकिन यदि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता रहा तो ऐसी प्राकृतिक घटनाओं के प्रभाव अधिक जटिल और गंभीर हो सकते हैं। इसलिए वास्तविक चुनौती अल नीनो से अधिक उस बदलती जलवायु व्यवस्था की है, जिसमें अल नीनो अपना प्रभाव डाल रहा है।

धरती हमें लगातार संकेत दे रही है। कभी रिकॉर्ड गर्मी के रूप में, कभी असामान्य बारिश के रूप में और कभी सूखे तथा बाढ़ के एक साथ बढ़ते खतरे के रूप में। अब आवश्यकता भय पैदा करने की नहीं, बल्कि समय रहते तैयारी करने की है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कायम किए बिना भविष्य सुरक्षित नहीं किया जा सकता।अल नीनो को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके प्रभावों से होने वाले नुकसान को कम करना निश्चित रूप से हमारे हाथ में है। इसके लिए वैज्ञानिक चेतावनियों को गंभीरता से लेना होगा, जलवायु अनुकूल नीतियां बनानी होंगी और प्रकृति के साथ विकास की नई भाषा लिखनी होगी। यदि हमने आज भी चेतावनियों को नजरअंदाज किया, तो आने वाली पीढ़ियों को केवल बदलते मौसम का नहीं, बल्कि बदलती और अधिक असुरक्षित दुनिया का सामना करना पड़ेगा। अब समय है कि धरती के बदलते मिजाज को समझा जाए और उसके संकेतों पर गंभीरता से अमल किया जाए।

सौरभ वार्ष्णेय
लेखक वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक,
राजनीतिक विचारक है।

संक्षिप्त वार्ता

नीट प्रदर्शनकारियों पर हुई एफआईआर होगी वापस

नई दिल्ली, 31 अगस्त (वेब वार्ता)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह नीट-यूजी परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कराने की मांग वाली केंद्र सरकार की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। केंद्र ने अदालत से उन छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल कर रद्द करने का आग्रह किया है जिनका पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो।

केंद्र ने तुरंत सुनवाई की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि पक्षकार आपस में समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। यह घटनाक्रम इसलिए अहम है क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने दिल्ली में 5 सितंबर को विरोध मार्च का आह्वान किया है। सीजेपी ने केंद्र सरकार पर 25 जुलाई को किए गए उन वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है।

डूसू चुनाव के लिए एबीवीपी ने 13 संभावित प्रत्याशियों की सूची की जारी

नई दिल्ली, 31 अगस्त (वेब वार्ता)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने आगामी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के लिए 13 संभावित प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिनके नाम इस प्रकार से हैं आलोक अत्री, आयुषी शर्मा, ईशु मौर्य, कृष्ण यादव, लक्ष्य राज सिंह, नितिन तंवर, प्रियांशु महामना, रिया छावड़ी, रिया मलिक, सनी डेढा, तान्या मावी, वरुण यादव, यश डबास हैं। ये सभी 13 प्रत्याशी आज से अलग-अलग परिसरों में छात्रों के मध्य जाकर प्रचार-प्रसार करेंगे। संगठन ने बयान जारी कर कहा है कि छात्रों के बीच निरंतर सक्रिय रहने वाले, संगठनात्मक रूप से मजबूत और छात्र हितों के लिए संघर्षरत कार्यकताओं को इस सूची में शामिल किया गया है।

उप महापौर ने सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश

नई दिल्ली, 31 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली नगर निगम के पूर्वी क्षेत्र में तेहबाजारी, अतिक्रमण व निर्माण कार्यों से जुड़ी समस्याओं को लेकर मुख्यालय में उप महापौर डॉ. मोनिका पंत ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उप महापौर ने कहा कि लोगों की सुविधा, सुगम आवागमन और व्यवस्थित बाजार व्यवस्था सुनिश्चित करना निगम की प्राथमिकता है। सार्वजनिक स्थानों के साथ मुख्य रूप से विकास मार्ग पर अतिक्रमण पर लगाम लगाई जाए। बैठक में आनंद विहार बस अड्डे पर तहबाजारी से जुड़ी समस्याओं की विस्तृत जानकारी ली गई। इस पर अधिकारियों को नियमों के अनुरूप प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बैठक में निर्माण व विकास कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।

पीपीपी मॉडल से दिल्ली को चमकाने के लिए कंपनियों से करार

नई दिल्ली, 31 अगस्त (वेब वार्ता)। राजधानी में सड़कों के विकास एवं सौंदर्यीकरण का कार्य दिल्ली सरकार द्वारा पीपीपी मॉडल के तहत करवाया जा रहा है। इसके तहत कंपनियां सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) फंड से सड़कों एवं फ्लाईओवर के नीचे की जगहों का सौंदर्यीकरण कर रही हैं। सोमवार को ऐसी ही दो कंपनियों के साथ दिल्ली सरकार ने करार किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह भी मौजूद रहे। रेखा गुप्ता ने कहा कि इस साझेदारी का उद्देश्य फ्लाईओवरों के नीचे और उनके आसपास मौजूद उपेक्षित अथवा कम उपयोग वाली जगहों को स्वच्छ, हरित, सुरक्षित और नागरिकों के लिए उपयोगी सार्वजनिक स्थलों में परिवर्तित करना है।

दिल्ली की मसौदा मतदाता सूची जारी

47.7 लाख नाम हटाए गए

नई दिल्ली,वेब वार्ता

दिल्ली की मसौदा मतदाता सूची सोमवार को प्रकाशित की गई, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के 1.45 करोड़ मतदाताओं में से 47.7 लाख के नाम काट दिए गए हैं।

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिन लोगों के नाम शामिल नहीं हैं, वे फॉर्म-छह और संबंधित दस्तावेजों के माध्यम से 30 सितंबर तक अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची चार नवंबर को जारी होगी। निर्वाचन आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, दावों और आपत्तियों की जांच की जाएगी और नोटिस तथा निपटारे की प्रक्रिया 29 अक्टूबर तक जारी रहेगी।

मसौदा सूची में लगभग 97.5 लाख मतदाता शामिल हैं, जिनके गणना प्रपत्र विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत 30 जून से शुरू होकर 17 अगस्त तक चले अभियान के दौरान प्राप्त और डिजिटल माध्यम से स्वीकार किए गए थे।

इस प्रक्रिया के दौरान दिल्ली के 1,45,10,299 मतदाताओं में से लगभग 67.18 प्रतिशत के फॉर्म डिजिटल माध्यम से भरे गए।

बाकी बचे 47.7 लाख मतदाताओं को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत्यु, सूची में एक बार से ज्यादा नाम और अन्य (एएसडीडीओ) श्रेणियों के तहत अनुपलब्ध के रूप में वगीर्कृत किया गया है और उनके नाम मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। डिजिटलीकरण का दायरा शहर की 70 विधानसभा सीट में काफी अलग-अलग रहा।

रोहिणी में सबसे अधिक 83.43 प्रतिशत फॉर्म डिजिटल माध्यम से भरे गए, जबकि तुगलकाबाद में यह आंकड़ा सबसे कम 52.15 प्रतिशत रहा। घर-घर जाकर गणना के माध्यम से मतदाता सूची तैयार करने के लिए एसआईआर का काम शुरू किया गया था। अभियान के दौरान जिन मतदाताओं के फॉर्म प्राप्त नहीं हुए थे, उन्हें दावा और आपत्ति प्रक्रिया के माध्यम से अपना नाम शामिल कराने की अनुमति दी गई है।

स्कूली बच्चों के साथ हुई अमानवीयता पर होगी सख्त कार्रवाई : रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, 31 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली में स्कूलों के मासूम बच्चों के साथ सामने आई अमानवीय घटनाओं पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कड़ा रुख अपनाया है। स्कूलों और स्कूली बसों में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए उन्होंने दोषी स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं में लापरवाही बरतने वाले स्कूल प्रबंधन और संबंधित जिम्मेदार लोगों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्ले स्कूल को सील करने के निर्देश भी जारी किए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों के साथ होने वाला अमानवीय व्यवहार किसी भी सभ्य समाज के लिए बेहद पीड़ादायक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और दोषियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कदम उठाए जाएं। जाफराबाद स्थित एक निजी डे-केयर एवं प्लेस्कूल में तीन वर्षीय बच्चे के साथ कथित शारीरिक एवं यौन दुर्व्यवहार की घटना पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की है और संबंधित स्कूल को सील करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि पीड़ित बच्चे के परिवार को कानूनी सहायता की आवश्यकता होगी तो दिल्ली सरकार उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने बवाना क्षेत्र में तीन वर्षीय नर्सरी छात्रा के साथ यौन शोषण की घटना पर भी गहरा दुख व्यक्त किया है। इस मामले में स्कूल बस चालक के कथित रूप से शामिल होने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही पर सवाल उठाया।

एलजी लिसनिंग पोस्ट नए पते पर शिफ्ट किया गया

उपराज्यपाल ने लिखा-अपने विचार और चिंताएं हमारे साथ साझा करते रहें

नई दिल्ली, 31 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से एलजी लिसनिंग पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की गई है।

दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, दिल्ली के नागरिकों के लिए एक अपडेट, एलजी लिसनिंग पोस्ट अब एक नए पते पर शिफ्ट हो गया है। उन्होंने नया लिंक सोशल मीडिया पर साझा किया है। उन्होंने लिखा, ह्लअपने विचार और चिंताएं हमारे साथ साझा करते रहें, क्योंकि हम मिलकर एक ज्यादा जवाबदेह और विकसित दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं।

बता दें कि दिल्ली के लोगों की शिकायतें अब तेजी से सुनी और सुलझाई जा रही हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने जनवरी से जून 2026 तक सिर्फ 6 महीने में 85 प्रतिशत से ज्यादा शिकायतों का निपटारा कर दिया है। उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू के ह्यजनता पहलेह्व वाले निदेर्शों के बाद डीडीए ने अपने काम करने का तरीका बदला। नतीजा ये हुआ कि साल की शुरूआत में डीडीए के पास लंबित शिकायतों की संख्या 22,946 थी, जो जून के अंत तक घटकर सिर्फ 3,167 रह गई। डीडीए के अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान सीपीजीआरएएमएस, एलजी लिसनिंग पोस्ट, सीएम जनसुनवाई, डीआरएमएस, मोबाइल 311 और समस्या निदान सेवा जैसे अलग-अलग प्लेटफॉर्म से आई कुल 19,779 शिकायतों का समाधान किया गया।

उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने पदभार संभालते ही सभी विभागों को कहा था कि काम में पारदर्शिता लाएं और जनता की समस्याओं को जल्दी सुलझाएं ताकि विकसित दिल्ली का लक्ष्य पूरा हो सके। डीडीए के अधिकारियों के साथ हुई पहली बैठक में ही उन्होंने खास तौर पर कहा था कि जनता की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और तुरंत निपटारा किया जाए। शिकायतें कम करने के लिए डीडीए ने हर कामकाजी सोमवार और गुरुवार को जनसुनवाई शुरू की। इस दिन बिना किसी अपॉइंटमेंट के आम लोग सीधे डीडीए दफ्तर आकर अपनी बात रख सकते हैं। डीडीए के उपाध्यक्ष ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिकायतों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दें। समय-समय पर समीक्षा बैठकें होती हैं और फील्ड यूनिट से लगातार फॉलोअप लिया जाता है ताकि कोई भी मामला ज्यादा दिनों तक लटका न रहे।

दिल्ली सरकार ने सौंदर्यीकरण को लेकर डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और कनोडिया ग्रुप के साथ किया एमओयू

नई दिल्ली, 31 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली सरकार ने स्वच्छ, हरित और सुंदर राजधानी के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और कनोडिया ग्रुप के साथ दिल्ली सचिवाल.य में सोमवार को समझौता ज्ञापत (एमओयू)पर हस्ताक्षर किए है। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, लोक निर्माण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पोस्ट करते हुए कहा कि इस साझेदारी के तहत फ्लाईओवरों के नीचे खाली स्थानों का सौंदर्यीकरण होगा, फुटपाथों की साफ-सफाई और बेहतर रखरखाव किया जाएगा, ग्रीन बेल्ट को संवारा जाएगा तथा पिलरों पर भारतीय संस्कृति, आधुनिक कला और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संदेश उकेरे जाएंगे।

साइकिल खरीद में कथित घोटाले को लेकर आआपा का दिल्ली सचिवालय के बाहर प्रदर्शन, जांच की मांग

नई दिल्ली, 31 अगस्त (वेब वार्ता)। आम आदमी पार्टी (आआपा) के कार्यकताओं ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकारी स्कूलों की छात्राओं के लिए साइकिल खरीद में कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग की। इस प्रदर्शन का नेतृत्व आआपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने किया।

प्रदर्शन के दौरान सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर साइकिलों की खरीद में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों की छात्राओं के लिए करीब 1.30 लाख साइकिलें 6,957 रुपये प्रति साइकिल की दर से खरीदी हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने खुले बाजार में लगभग 4,000 रुपये में समान गुणवत्ता की साइकिल खरीदने का दावा किया है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में गरीब परिवारों की छात्राओं को वितरित की जाने वाली साइकिलों की खरीद में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने करीब 1.30 लाख साइकिलों की खरीद पर लगभग 90 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि बाजार कीमत के आधार पर इसमें करीब 40 करोड़ रुपये के कथित भ्रष्टाचार का सवाल उठता है। उन्होंने कहा कि बाजार में एक सामान्य साइकिल की कीमत करीब 4,000 रुपये है, जबकि दिल्ली सरकार ने प्रति साइकिल लगभग 7,000 रुपये खर्च किए। भारद्वाज ने इस पूरे मामले की जांच कराने और खरीद प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जिम्मेदारी तय करने की मांग की।

आआपा नेता ने आरोप लगाया कि जिन गरीब बच्चियों को सरकारी योजना के तहत साइकिलें मिलनी थीं, उनके लिए की गई खरीद में भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और खरीद से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने चाहिए। प्रदर्शन में आआपा के बुराड़ी विधायक संजीव झा, कोंडली विधायक कुलदीप कुमार समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

नौकरी का झांसा देकर दो महिलाओं को देह व्यापार में धकेला

नई दिल्ली, 31 अगस्त (वेब वार्ता)। नौकरी दिलाने का झांसा देकर दिल्ली लाई गईं दो महिलाओं को जीबी रोड स्थित कोठे पर बेचकर जबरन देह व्यापार कराने का मामला सामने आया है। कमला मार्केट पुलिस ने शनिवार को दोनों महिलाओं को मुक्त कराया। पुलिस ने केस दर्ज कर तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इनमें कोठा संचालिका गीता, मंजू और पारो खातून शामिल हैं। पुलिस अब एक आठ वर्षीय बच्चे की तलाश कर रही है।

स्लीपर बस में 16 वर्षीय छात्रा से गैंगरेप

पुलिस ने आरोपी ड्राइवर-कंडक्टर को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, 31 अगस्त (वेब वार्ता)। राजधानी दिल्ली एक बार फिर शर्मशार हुई है। एक स्लीपर बस में 16 वर्षीय छात्रा के साथ कथित तौर पर गैंगरेप की घटना हुई। इस मामले में पुलिस ने बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार किया है।

बताया गया है कि यह घटना कश्मीरी गेट इलाके में 4 अगस्त की रात को हुई थी। फिलहाल, मामले में पुलिस ने बस के ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप को गिरफ्तार किया है। पीड़िता उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की रहने वाली है और 11वीं कक्षा की छात्रा है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, छात्रा परिजनों से नाराज होकर बिना बताए घर से निकल गई थी और नोएडा में रहने वाले अपने चचेरे भाई के पास जा रही थी। भारी बारिश और अंधेरे के कारण छात्रा गलती से ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर उतर गई। इसी दौरान एक खाली स्लीपर बस वहां से गुजरी। छात्रा ने बस को रुकने का इशारा किया, जिसके बाद बस रुक गई। ड्राइवर-कंडक्टर ने उसे नोएडा सेक्टर-63 जाने की बात कहकर बस में बैठा लिया।

आरोप है कि बस चलने के कुछ देर बाद कंडक्टर ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकत शुरू कर दी। पीड़िता के मुताबिक, इसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर ने उसके साथ रेप किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी पीड़िता को देर रात कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास रिंग रोड पर उतारकर फरार हो गए। घबराई हुई छात्रा ने कश्मीरी गेट पुलिस से संपर्क कर पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को तिमारपुर की एक बस पार्किंग से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल स्लीपर बस को जब्त कर लिया है और उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी बस में खराबी आने के बाद बस को सूरजपुर की वर्कशॉप में रिपेयरिंग के लिए लेकर गए थे। बस की रिपेयरिंग के बाद ड्राइवर और कंडक्टर खाली बस लेकर तिमारपुर जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर छात्रा मिली। परी चौक से कश्मीरी गेट तक करीब 47 किलोमीटर का सफर बस ने तय किया। बस स्लीपर होने और पर्दे लगे होने के कारण किसी भी राहगीर को बस के अंदर का दिखाई नहीं दिया था।

जमानत कार्यवाही प्रभावित करने की कोशिश के मामले में ठग सुकेश चंद्रशेखर को आठ साल की जेल

नई दिल्ली, 31 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली की एक अदालत ने ठग सुकेश चंद्रशेखर को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनकर एक अन्य आपराधिक मामले में जमानत की कार्यवाही को प्रभावित करने की कोशिश के मामले में आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

तीस हजारी अदालत की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्षिता मिश्रा ने चंद्रशेखर को भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धारा 170 के तहत दो साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के जुमार्ने, धारा 189 के तहत दो साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के जुमार्ने तथा धारा 507 के तहत चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। यह आदेश 29 अगस्त को आया, जिसे सोमवार को उपलब्ध हुआ है। इसमें अदालत ने कहा, ह्यसजा से यह स्पष्ट होना चाहिए कि आपराधिक न्याय व्यवस्था एक बार किए गए सामान्य गैरकानूनी कृत्य और सार्वजनिक संस्थाओं के कामकाज को जानबूझकर प्रभावित करने, डराने या उसमें दखल देने के लिए लगातार और सुनियोजित तरीके से किए गए कृत्यों के बीच अंतर करती है।

अदालत ने निर्देश दिया कि तीनों सजाएं एक के बाद एक लगातार चलेंगी, जिससे कुल जेल की सजा आठ साल होगी। जुमार्ना नहीं भरने की स्थिति में चंद्रशेखर को एक महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने 20 अगस्त को चंद्रशेखर को भादंसं की धारा 170, 189 और 507 के तहत दोषी ठहराया था। ये धाराएं किसी अन्य व्यक्ति या पदाधिकारी का रूप धारण करने तथा धमकी देने से संबंधित हैं। सजा संबंधी आदेश के अनुसार, चंद्रशेखर ने 28 अप्रैल, 2017 को न्यायिक अधिकारी पूनम चौधरी को कई फोन किए थे। उसने खुद को दक्षिण भारत से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बताया और अपने दावे को विश्वसनीय बनाने के लिए उसी क्षेत्र के लहजे में बात की।

अदालत ने कहा कि उसका उद्देश्य एक अन्य आपराधिक मामले में अपनी जमानत से जुड़ी न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित करना था। अदालत ने उसके इस कृत्य को न्यायिक प्रक्रिया की शुचिता और निष्पक्षता पर हमला बताया। अदालत ने कहा, ह्यजिस व्यक्ति का रूप धारण किया गया, उसका चयन संयोग से नहीं हुआ था।ह्व अदालत के मुताबिक, चंद्रशेखर ने जानबूझकर संवैधानिक पद से जुड़ी विश्वसनीयता का लाभ उठाने की कोशिश की।

अदालत ने इस दलील को भी खारिज कर दिया कि न्यायिक अधिकारी को धोखा देने या जमानत हासिल करने में नाकाम रहने को सजा कम करने के आधार के रूप में देखा जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि कोशिश असफल हो जाने से किसी दूसरे व्यक्ति का रूप धारण करने का कृत्य कम गंभीर या महत्वहीन नहीं हो जाता। अदालत ने यह भी कहा कि सुनवाई के दौरान चंद्रशेखर ने वास्तव में अपने कृत्य पर कोई पछतावा या पश्चाताप नहीं दिखाया, बल्कि शिकायतकर्ता न्यायिक अधिकारी की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठाए।

अदालत ने कहा कि मौजूदा तकनीकी दौर में यह मामला विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि डीपफेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से तैयार ऑडियो-वीडियो सामग्री, किसी व्यक्ति की आवाज की हूबहू नकल और फर्जी तरीके से भेजे गए संदेश या संचार का इस्तेमाल करके संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों का रूप धारण करना पहले की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय बनाया जा सकता है अदालत ने कहा, ह्यइस मामले में सुनाई जाने वाली सजा में निश्चित रूप से निवारक संदेश होना चाहिए।

बस में नाबालिग से गैंग रेप की घटना जघन्य अपराध, आरोपियों को मिलेगी कड़ी सजा: लता गुप्ता

नई दिल्ली, 31 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष लता गुप्ता ने 4 अगस्त की रात स्लीपर बस में 16 वर्षीय लड़की के साथ हुए कथित गैंग रेप की कड़ी निंदा की और आरोपियों के लिए त्वरित सुनवाई और शीघ्र सजा की मांग की।

लता गुप्ता ने कहा, ह्लबस में बच्ची से गैंग रेप बहुत ही जघन्य अपराध है। इस मामले में पुलिस ने बस ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। आयोग की ओर से पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक में सुनवाई हो, इसके लिए आयोग अपनी बात रखेगा।

लता गुप्ता ने आगे कहा, ह्लमुझे लगता है कि नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है। हम अधिकार की बात करते हैं लेकिन कर्तव्य भूल रहे हैं। इस प्रकार की घटना बेहद निंदनीय हैं। ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सराकर ने फास्ट ट्रैक अदालत के साथ कई कदम उठाए हैं। पुलिस के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की रहने वाली 11वीं कक्षा की छात्रा परिजनों से नाराज होकर बिना बताए घर से निकल गई थी और नोएडा में रहने वाले अपने चचेरे भाई के पास जा रही थी। भारी बारिश और अंधेरे के कारण छात्रा गलती से ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर उतर गई। इसी दौरान एक खाली स्लीपर बस वहां से गुजरी। छात्रा ने बस को रुकने का इशारा किया, जिसके बाद बस रुक गई। ड्राइवर-कंडक्टर ने उसे नोएडा सेक्टर-63 जाने की बात कहकर बस में बैठा लिया।

दिल्ली के निजी स्कूल में 3 साल की बच्ची का यौन शोषण

नई दिल्ली, 31 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली के बवाना इलाके के एक स्कूल में तीन साल की छात्रा के यौन शोषण का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्कूल बस के ड्राइवर विकास ने बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर उसके साथ कई बार गलत टच किया था। फिलहाल, इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

दिल्ली पुलिस ने सोमवार को बताया कि स्कूल बस के ड्राइवर विकास ने बच्ची का यौन शोषण किया था। पीड़िता की मां ने बच्ची से पूछताछ की तो उसने स्कूल में मौजूद एक ह्यबैड अंकलह्व के बारे में बताया, जो उसे चॉकलेट देता था। बच्ची आरोपी का नाम नहीं बता पा रही थी, जिसके बाद परिजनों ने स्कूल प्रशासन को मामले की जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, 24 अगस्त को स्कूल में बच्ची को फोटो और सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई, जिसे देखकर बच्ची ने आरोपी ड्राइवर विकास की पहचान की। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पोक्सो एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई।

बाद में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी विकास को स्कूल परिसर से गिरफ्तार का लिया। जांच में सामने आया कि आरोपी करीब 8 महीने से स्कूल में कैब चला रहा था। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को जेब में चॉकलेट लेकर घूमते हुए देखा गया। आरोप है कि ड्राइवर ने बच्ची के बाथरूम जाते समय उसका पीछा किया, चॉकलेट दी और सीढ़ियों के नीचे उसके साथ गलत जगह पर टच किया।

मिले हैं वीडियो

पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन जब्त किया है, जिसमें छोटे बच्चों को चॉकलेट खिलाते हुए कई वीडियो मिले हैं। वीडियो में दिखाई दे रहे बच्चों की पहचान और काउंसलिंग कराई जा रही है। स्कूल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी पुलिस ने कब्जे में ले ली है। इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने कश्मीरी गेट इलाके में एक नाबालिग से कथित गैंगरेप मामले में एक स्लीपर बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार किया। लड़की ग्रेटर नोएडा से बस में बैठकर दिल्ली पहुंची थी। आरोप है कि रात के समय ड्राइवर और कंडक्टर ने कथित तौर पर उसका गैंगरेप किया।

दिल्ली पुलिस ने आदर्श नगर में अवैध रूप से रहने वाले एक बांग्लादेशी नागरिक को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, वेब वार्ता

दिल्ली पुलिस ने सोमवार को बांग्लादेशी नागरिक होने के संदेह में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज मामले के सिलसिले में की गई है।

आरोपी की पहचान मोहम्मद अत्रुल रहमान के तौर पर हुई है, जो मोहम्मद अब्दुल का बेटा है और जिला सतखीरा, बांग्लादेश का रहने वाला है। उसे आदर्श नगर पुलिस स्टेशन के स्टाफ ने उसकी पत्नी से मिली जानकारी के आधार पर शुरूआती जांच के बाद गिरफ्तार किया। पत्नी का आरोप था कि वह बांग्लादेशी नागरिक है और फर्जी पहचान दस्तावेजों के आधार पर भारत में रह रहा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 24 अगस्त को आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में घरेलू हिंसा की घटना के बारे में एक पीसीआर कॉल आई थी। कॉल करने वाली निक्की, जो मोहम्मद अत्रुल की पत्नी है, उसने आरोप लगाया कि उसके पति ने उसके साथ मारपीट की थी।

आदर्श नगर के एसएचओ की जांच के दौरान, शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका पति कथित तौर पर बांग्लादेशी नागरिक है और फर्जी पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल करके भारत में रह रहा था। उसने कहा कि वह कथित फर्जी दस्तावेजों और उसकी बांग्लादेशी नागरिकता से जुड़े अन्य दस्तावेजों के साथ एक विस्तृत लिखित शिकायत सौंपेगी। 28 अगस्त को, शिकायतकर्ता ने आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में संबंधित दस्तावेजों के साथ अपनी लिखित शिकायत सौंपी।

शुरूआती जांच के दौरान, उसने बताया कि अत्रुल ने पहले शाइस्ता परवीन नाम की महिला से शादी की थी और वह उसकी दूसरी पत्नी है। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसने एक बांग्लादेशी महिला, मनीरा खातून से तीसरी शादी की थी, जो रूहल अमीन की बेटी है और उपजिला सतखीरा, बांग्लादेश की रहने वाली है। शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए शादी के समझौते/दस्तावेज के अनुसार, कथित व्यक्ति का विवरण अत्रुल रहमान, पिता मोहम्मद अब्दुल, निवासी अलीपुर, उपजिला सतखीरा, बांग्लादेश के तौर पर दर्ज था।

पुलिस ने कहा कि आरोपों की जांच कानून के मुताबिक की जा रही है और सभी जरूरी सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। शुरूआती जांच के दौरान, शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए दस्तावेजों और जानकारी की जांच की गई और जरूरी तस्दीक की गई। शुरूआती जांच और इकट्ठा की गई जानकारी के आधार पर, आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में मोहम्मद अत्रुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस ने बताया कि आगे की जांच चल रही है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की जांच के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की जाएगी। साथ ही, उसकी नागरिकता, पहचान के दस्तावेजों, इमिग्रेशन हिस्ट्री और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की पुष्टि करने सहित सभी संभावित सबूत इकट्ठा किए जाएंगे। पुलिस ने कहा कि संबंधित अधिकारियों से पुष्टि के बाद, उसकी कथित विदेशी नागरिकता और इमिग्रेशन स्टेटस के संबंध में कानून के अनुसार जरूरी कार्रवाई की जाएगी।

संक्षिप्त वार्ता

जीआरपी ने एक लाख की अवैध शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार

वेब वार्ता, कानपुर। जीआरपी पुलिस ने एक लाचख की अवैध शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। तस्कर के पास ब्रांडेड शराब की लगभग 27 लीटर शराब बरामद की। प्रभारी निरीक्षक थाना जीआरपी कानपुर सेन्ट्रल ओम नारायण सिंह ने बताया कि दोपहर 12.10 बजे कानपुर सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन गोविन्दपुरी के प्लेटफार्म नं0 01 हावडा इण्ड के आगे खम्भा नं0 1020/29। के पास से चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त पाण्डव कुमार पुत्र इन्द्रदेव यादव निवासी ग्राम सितुआहा वार्ड नं0 1 थाना सलखुआ जनपद सहरसा बिहार को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से 3 पिट्ठू बैग मे कुल पच्चीस (36) बोतल यानी कुल 27 लीटर अंग्रेजी अवैध शराब बरामद हुई। जिसकी अनुमानित कीमत करीब एक लाख रू0 से अधिक है। पुलिस ने बताया कि पूछतांछ में अभियुक्त ने बताया कि वह अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा से लाकर बिहार जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा था। अभियुक्त से अन्य सदस्यों की जानकारी व अन्य जनपदों तथा प्रान्तों से आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। पकडने वाली टीम में एसआई धीरेन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी चौकी गोविन्दपुरी थाना जीआरपी कानपुर सेन्ट्रल, हे0का0 वीरेन्द्र कुमार, शिव सिंह, सत्येन्द्र सिंह, वैश खान, राज कमल वर्मा थाना जीआरपी कानपुर सेन्ट्रल रहे।

हरदोई के प्रसिद्ध मिर्चा राम स्वीट्स पर खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी और असुरक्षित खाद्य सामग्री की बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जनपद में लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ शहर के नामचीन मिठाई एवं स्नैक्स प्रतिष्ठान मिर्चा राम स्वीट्स पर अचानक छापेमारी की। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों की गंभीर अनदेखी सामने आई। भारी गंदगी और अस्वच्छ परिस्थितियां पाए जाने पर विभाग ने तत्काल प्रभाव से कारोबार बंद कराने के निर्देश दिए।

खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान के फ्रिज के अंदर चूहों का कब्जा पाया गया। फ्रिज और परिसर के कई हिस्सों में काला फफूंद (ब्लैक फंगस) भी लगा मिला। इससे खाद्य पदार्थों के सुरक्षित रख-रखाव पर गंभीर सवाल खड़े हुए। टीम को परिसर में कई स्थानों पर अत्यधिक गंदगी मिली। कच्चा माल भी साफ-सफाई का ध्यान रखे बिना गंदगी के बीच बेतरतीब ढंग से रखा हुआ पाया गया।फर्श पर भरा मिला गंदा पानी निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान के फर्श पर कई जगह गंदा पानी भरा मिला। किचन की स्थिति भीसंतोषजनक नहीं पाई गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि रसोईघर में भारी गंदगी थी और तैयार खाद्य पदार्थों को खुले में रखा गया था। इससे खाद्य पदार्थों के दूषित होने की आशंका बनी हुई थी।टीम ने खाद्य पदार्थों की तैयारी के दौरान सिंथेटिक कलर के अत्यधिक इस्तेमाल की भी बात कही है। अधिकारियों ने मौके पर खाद्य पदार्थों के रखरखाव, स्वच्छता, कच्चे माल की स्थिति तथा निर्माण प्रक्रिया का निरीक्षण किया और पाई गई कमियों को गंभीरता से लिया।

गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि, 3 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हो रही बढ़ोत्तरी, चेतावनी बिंदु से

वाराणसी, 29 अगस्त (वेब वार्ता)। गंगा के जलस्तर में एक बार फिर तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की ओर से शनिवार की दोपहर 12 बजे जारी रीडिंग के अनुसार वाराणसी के राजघाट गेज साइट पर गंगा का जलस्तर 68.16 मीटर दर्ज किया गया। जलस्तर फिलहाल तीन सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, जिससे नदी किनारे रहने वाले लोगों और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है।

सीडब्ल्यूसी के आंकड़ों के मुताबिक राजघाट पर गंगा का चेतावनी स्तर 70.262 मीटर निर्धारित है, जबकि खतरे का निशान 71.262 मीटर है। शनिवार दोपहर दर्ज जलस्तर खतरे के निशान से करीब 3.10 मीटर नीचे है। वहीं चेतावनी बिंदु से यह करीब 2.10 मीटर नीचे है। हालांकि जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है।

प्रयागराज में फिर बढ़ा गंगा-यमुना का जलस्तर, 24 घंटे में एक मीटर तक की बढ़ोतरी

प्रयागराज, 29 अगस्त (वेब वार्ता)। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर में एक बार फिर तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जिला प्रशासन की ओर से शनिवार सुबह आठ बजे जारी जलस्तर की रिपोर्ट के अनुसार, यमुना के नैनी और गंगा के छतनाग में पिछले 24 घंटे के दौरान करीब एक मीटर की वृद्धि हुई है। हालांकि, अभी सभी तटबंध सुरक्षित बताए गए हैं।

जिला प्रशासन के अनुसार यमुना नदी का जलस्तर नैनी में 80.68 मीटर दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में इसमें 103 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान क्षेत्र में 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। गंगा नदी का जलस्तर फाफामऊ में 80.69 मीटर रहा। यहां पिछले 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई और 16.8 मिलीमीटर बारिश हुई। इसी तरह छतनाग में गंगा का जलस्तर 80.16 मीटर दर्ज किया गया। यहां 24 घंटे में जलस्तर 98 सेंटीमीटर बढ़ा है। छतनाग क्षेत्र में 20.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं, एसटीपी बक्सी बांध क्षेत्र में जलस्तर 80.86 मीटर दर्ज किया गया, जिसमें पिछले 24 घंटे में 96 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। जिला प्रशासन के मुताबिक गंगा और यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी पर लगातार नजर रखी जा रही है। संबंधित विभागों और अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश हैं। प्रशासन ने बताया कि जिले के सभी तटबंध फिलहाल सुरक्षित हैं।

देवरिया में बोले सीएम योगी, 'एक परिवार के पांच सांसदों वाली पार्टी का भी जनता पार्टी जैसा हाल होगा

वेा वार्ता, देवरिया

एक ही परिवार के पांच सांसद होने को लेकर समाजवादी पार्टी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि पार्टी इसलिए बची हुई है क्योंकि एक ही परिवार के पांच सांसद हैं। घबराइए मत, इनका हाल भी जनता पार्टी जैसा होने वाला है।

देवरिया में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण-शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सपा पर परिवार केंद्रित राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार लेने के लिए नहीं, देने के लिए आयोजन कर रही है। अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन्होंने तंज कसा कि जब वह उद्घाटन करने जा रहे थे तो ह्यबबुआह्न की नींद टूट गई और वह आनन-फानन में प्रेस कांफ्रेंस करने लगे।

मुख्यमंत्री ने सपा सरकार के कार्यकाल को भी निशाने पर लिया। जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल का उदाहरण देते हुए कहा कि परियोजना की लागत करीब 200 करोड़ रुपये थी, लेकिन सपा सरकार में 817 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए और इसके बावजूद परियोजना पूरी नहीं हुई। इसे पूरा करने के लिए अब भी करीब 150 से 200 करोड़ रुपये और खर्च करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यह जनता की गाढ़ी कमाई है, किसी ह्यसैफई सिंडिकेटह्न की नहीं। सरकारी खजाने पर बोझ डालने के लिए निजी कंपनी बनाने की कोशिश को भी उन्होंने साजिश बताया।

योगी ने परिवारवाद के मुकाबले अपनी सरकार के कामकाज को राजनीतिक आधार बनाया। कहा कि गरीब को बिना भेदभाव राशन और सरकारी योजनाओं का लाभ मिले तथा नौजवान को रोजगार और नियुक्ति पत्र मिले, यही वास्तविक सुशासन है। सरकार की विभिन्न योजनाओं से युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने, डिजिटल एंटरप्रेन्योर और ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात भी कही।

युवाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार दो करोड़ युवाओं को टैबलेट उपलब्ध कराने का लक्ष्य लेकर चल रही है। तकनीक के माध्यम से शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ नौकरियों का खजाना खोलने का दावा उन्होंने किया।

क्षेत्रीय राजनीति को साधते हुए मुख्यमंत्री ने भाटपाररानी के विधायक सभा कुंवर के प्रस्ताव पर क्षेत्र के सभी फ्लाईओवर निर्माण प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के परिश्रम और पुरुषार्थ से देवरिया विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मीडिया की भूमिका पर भी मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। सरकार से सवाल पूछना और समाज की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना उसका दायित्व है। मीडिया की आवाज दबाने के बजाय उसके सवालों का सम्मान किया जाना चाहिए।

बिना भेदभाव लोगों तक पहुँचा जा रहा है

उन्होंने कहा कि प्रदेश की तस्वीर और पहचान बदल चुकी है। अब उत्तर प्रदेश को कोई बीमारू राज्य नहीं कहता। प्रदेश में माफिया राज समाप्त हुआ है और दंगे-फसाद पर प्रभावी नियंत्रण है। इंसेफेलाइटिस जैसी घातक बीमारी पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने का दावा करते हुए उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले गरीबों को आवास, शौचालय, रसोई गैस और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं आसानी से नहीं मिलती थीं। गरीबों के हिस्से का राशन तक बेच दिया जाता था और व्यवस्था माफिया के हवाले थी। अब सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव लोगों तक पहुंचाया जा रहा है।

बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंचे डीएम-एसपी

ग्रामीणों से संवाद कर जानी समस्याएं

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। जिलाधिकारी अनुनय झा एवं पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने शनिवार को बिलग्राम तहसील के बाढ़ प्रभावित वाण एवं जरैला गांवों का निरीक्षण कर जमीनी स्थिति का जायजा लिया। दोनों अधिकारियों ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं और उनकी आवश्यकताओं की जानकारी ली।

जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से खाद्य सामग्री, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं और आवागमन की स्थिति के बारे में जानकारी ली। पशुपालकों से पशुओं के लिए भूसा एवं चारे की उपलब्धता भी पूछी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित परिवारों तक राहत सामग्री समय से पहुंचे और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में किसी प्रकार की कमी न होने पाए।

इस दौरान डीएम-एसपी ने प्रभावित लोगों को राहत सामग्री एवं आवश्यक दवाओं का वितरण भी किया। जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ की स्थिति पर प्रशासन की लगातार नजर है। राहत एवं बचाव कार्य पूरी तत्परता से संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को गांवों में नियमित भ्रमण कर समस्याओं का तत्काल समाधान कराने तथा जरूरत के अनुसार राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी लेते हुए पुलिस अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बनाए रखने और जरूरत पड़ने पर ग्रामीणों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी बिलग्राम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

तेज रफ्तार बाइक पिकअप में घुसी

18 वर्षीय युवक की मौके पर मौत

वेबवार्ता/हरदोई। शनिवार को पाली क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। किर्तियापुर पुलिया के पास अनियंत्रित बाइक सामने से मोड़ रहे पिकअप वाहन के पिछले हिस्से में जा घुसी। हादसे में बाइक सवार 18 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके चचेरे भाई और बहनोई गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद पिकअप चालक वाहन लेकर फरार हो गया।

सवायजपुर थाना क्षेत्र के जैतीपुर गांव निवासी परमेश्वर दीन उर्फ अजीत (18) पुत्र रामासरे शनिवार को पाली कस्बे में मीट खरीदने आया था। उसके साथ बाइक पर चचेरा भाई महावीर और बहनोई हाकिम निवासी ग्राम अरुआ खानपुर, शाहजहांपुर भी सवार थे। मीट खरीदने के बाद तीनों बाइक से वापस गांव लौट रहे थे।

बताया जाता है कि कितियापुर पुलिया के पास पिकअप चालक वाहन को मोड़ रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही बाइक अनियंत्रित होकर पिकअप के डाले में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार परमेश्वर दीन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महावीर और हाकिम गंभीर रूप से घायल हो गए।

चचेरे भाई और बहनोई गंभीर घायल, हादसे के बाद पिकअप चालक फरार

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। राहगीरों ने घायलों को तत्काल पीएचसी पाली पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

सूचना मिलते ही पाली थाने के उपनिरीक्षक अतुल शर्मा व घनश्याम बिंद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे की खबर मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस फरार पिकअप चालक की तलाश के साथ ही दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।

बैंक डाकघरों में पुलिस की सघन चेकिंग, साइबर फ्रॉड से बचाव को लेकर लोगों को किया जागरूक

वेब वार्ता, बलरामपुर

पुलिस अधीक्षक बलरामपुर मार्तण्ड प्रकाश सिंह के निर्देशानुसार बैंकों / डाकघर /जनसेवा केन्द्र व अन्य वित्तीय संस्थानों की सुरक्षार्थ जनपद बलरामपुर के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / चौकी प्रभारी व मिशन शक्ति टीम द्वारा बैंकों / डाकघर व अन्य वित्तीय संस्थानों में चेकिंग अभियान चलाया गया । जिसके क्रम में जनपद बलरामपुर के समस्त थानों की पुलिस द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों में पड़ने वाले बैंकों/ डाकघर के

आस पास तथा बैंक के अन्दर सघन चेकिंग की गई। इस दौरान बैंक अधिकारियों/कर्मचारियों से वार्ता कर सुरक्षा के सभी उपकरण सीसीटीवी कैमरा, फायर अलार्म आदि को किया चेक। संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों को चेक किया गया तथा बैंक में मौजूद लोगों को सुरक्षा के दृष्टिगत जागरुक किया गया एवं बैंक ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों को सतर्क रहते हुए संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान सभी को साइबर अपराध से बचाव के बारे में भी जानकारी दी गई।

नेपाल में आई बाढ़ के कारण गंडक/नारायणी नदी क्षेत्र से प्राप्त 06 अज्ञात शवों के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्रवाई जारी

कुशीनगर 29 अगस्त। कुशीनगर जिले के अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा ने बताया कि नेपाल में आई बाढ़ के कारण जनपद कुशीनगर में गंडक/नारायणी नदी के क्षेत्र से अब तक कुल 06 अज्ञात शव प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में इन शवों की पहचान पूर्ण रूप से नहीं हो सकी है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन कुशीनगर द्वारा सभी शवों को ससम्मान जिला अस्पताल, कुशीनगर के डीप फ्रीजर में सुरक्षित रखा गया है, ताकि पहचान एवं आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण होने तक शवों का सुरक्षित संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। शवों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा नेपाल के सीमावर्ती संबंधित जिला प्रशासन एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ निरंतर समन्वय एवं वार्ता की जा रही है। साथ ही, शवों की पहचान एवं उनके परिजनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

ईपीएफओ में ईईसी-2026 हुआ लागू

वेब वार्ता, कानपुर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कर्मचारी नामांकन अभियान ,2026 को प्रभावी रूप से लागू करने तथा सामाजिक सुरक्षा के दायरे से छूटे पात्र कर्मचारियों को पुनः जोड़ने के उद्देश्य से क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-क शाहिद इकबाल द्वारा प्रतिष्ठानों के कर्मचारी रेमिटेंस एवं चालानों की स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पूर्व की तुलना में कई प्रतिष्ठानों में चालानों में दर्शाए गए कर्मचारियों की संख्या में कमी पाए जाने के तथ्य सामने आए। इस पर शाहिद इकबाल द्वारा संबंधित प्रतिष्ठानों की स्थिति की समीक्षा कर कर्मचारी कवरेज में आई कमी को दूर करने तथा छूटे हुए पात्र कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर द्वारा 1,160 प्रतिष्ठानों को पत्र जारी किए गए हैं। इन पत्रों के माध्यम से प्रतिष्ठानों को अपने वर्तमान कर्मचारी रेमिटेंस एवं चालानों की समीक्षा करने तथा यदि कोई पात्र कर्मचारी ईपीएफओ कवरेज से छूट गया है और वर्तमान में कार्यरत है, तो उसे सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देशित एवं जागरूक किया गया है। ईपीएफओ द्वारा जारी किए गया पत्र विशेष रूप से विभिन्न औद्योगिक क्लस्टरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित प्रतिष्ठानों को भेजे गए हैं। इनमें उन्नाव का लेदर क्लस्टर, पनकी-दादानगर, रूमा, जाजमऊ, कानपुर देहात, फतेहपुर औद्योगिक क्षेत्र, झांसी सहित अन्य औद्योगिक क्षेत्र एवं

क्लस्टर शामिल हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठानों को उनके वर्तमान कर्मचारी रेमिटेंस की समीक्षा करने तथा यदि कोई पात्र कर्मचारी कवरेज से छूट गया है तो उसे सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए प्रेरित करना है। अभियान के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों एवं शर्तों के अधीन कर्मचारी अंशदान से संबंधित विशेष छूट का लाभ उपलब्ध है। ऐसे मामलों में निर्धारित शर्तों के अनुसार कर्मचारी अंशदान की वसूली से छूट का प्रावधान है। नियोक्ता को नियमानुसार अपना अंशदान तथा देय ब्याज एवं प्रशासनिक प्रभार 100 का भुगतान करना होगा। इस प्रकार ईईसी-2026 प्रतिष्ठानों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसके माध्यम से वे अपने यहाँ कार्यरत ऐसे कर्मचारियों को, जो पूर्व में किसी कारणवश ईपीएफओ के दायरे से छूट गए थे, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ सकते हैं।इससे कर्मचारी कवरेज में आई कमी को दूर करने तथा अधिक से अधिक पात्र कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

प्रिंसिपल एम्प्लॉयर भी निभाएं महत्वपूर्ण भूमिका

ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर द्वारा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को भी इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। विशेष रूप से नगर निगम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा अन्य प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, जिनके प्रतिष्ठानों अथवा संस्थानों में ठेकेदारों के माध्यम से कर्मचारी कार्यरत हैं, यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके अधीन कार्यरत कोई भी पात्र कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर न रहे। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अपने यहाँ कार्यरत ठेकेदारों के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं तथा यदि कोई पात्र कर्मचारी छूट गया है तो ईईसी-2026 के माध्यम से उसका नामांकन सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं।ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर की इस पहल का उद्देश्य प्रतिष्ठानों में कर्मचारी कवरेज को बेहतर बनाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना तथा ह्लकोई भी पात्र कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा से वंचित न रहेह्न के उद्देश्य को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाना है।

31 वर्षों से निभा रहे भाई-बहन के स्नेह का रिश्ता

नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने बहनों से बंधवाई राखी

कुशीनगर। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर पडरौना नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने अपने मोहल्ले साहबगंज तुरहा टोली में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 31वें वर्ष बहनों से राखी बंधवाकर भाई-बहन के अटूट प्रेम और स्नेह की परंपरा को आगे बढ़ाया।

इस अवसर पर छोटी-छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी बहनों तक ने नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल की कलाई पर राखी बांधी और उन्हें अपना स्नेह व आशीर्वाद दिया। बहनों के स्नेह और आत्मीयता से पूरा माहौल भावुक एवं उल्लासपूर्ण रहा। नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने कहा कि 31 वर्षों से रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों से राखी बंधवाना उनके लिए केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भावनाओं और आत्मीय रिश्तों का पर्व है। बहनों का प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी बहनों तक का अपनापन उन्हें हमेशा नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है।

विशेष उत्साह देखने को मिला

उन्होंने सभी बहनों के सुख, समृद्धि एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी बहनों के जीवन में सदैव खुशियां बनी रहें और भाई-बहन का यह पवित्र रिश्ता इसी तरह प्रेम एवं विश्वास के साथ मजबूत होता रहे। इस दौरान मोहल्ले की बहनों एवं स्थानीय नागरिकों में रक्षाबंधन को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला।

कुशीनगर में गंडक में पानी का डिस्चार्ज बढने से छितौनी बांध को खतरा

कुशीनगर 29 अगस्त।कुशीनगर में नेपाल में आई बाढ़ के वक्त गंडक में डिस्चार्ज बढ़कर करीब डेढ़ लाख क्यूसेक पहुंच गया था। अगले दिन गुरुवार को डिस्चार्ज घटने से खड्डा रेता क्षेत्र में बाढ़ का खतरा टल गया था। शुक्रवार को नदी का डिस्चार्ज फिर बढ़ने लगा। गुरुवार के 88 हजार क्यूसेक के सापेक्ष शुक्रवार को डिस्चार्ज बढ़कर 1 लाख 2 हजार क्यूसेक हो गया। इसका असर यह है कि नदी छितौनी बांध के भेडियारी ठोकर नम्बर तीन के समीप दबाव बना रही है। बांध के संवेदनशील प्वाइंट्स पर खतरा बढ़ गया है। हालांकि, बाढ़ खंड विभाग का दावा है कि इतने डिस्चार्ज से बाढ़ का खतरा नहीं है।

बाढ़ में बहकर तीन और लाशें आईं

नेपाल से बाढ़ में बहकर आईं तीन और लाशें शुक्रवार को गंडक नदी से बरामद हुईं। कुशीनगर जिले के खड्डा इलाके में दो महिलाओं और एक पुरुष का शव पाया गया। कुल अब तक छ शवों को प्रशासन ने एसडीआरएफ की मदद से शवों को निकलवाकर सुरक्षित मोर्चरी में रखवा दिया है। गुरुवार को भी तीन लाशें मिली थीं, जिन्हें मोर्चरी में रखवाया गया है। सभी छह शवों के बारे में नेपाल प्रशासन को जानकारी दे दी गई है। जिले की मोर्चरी के फ्रीजर में छह लाशें रखे जाने की ही जगह है।

नेपाल से नदी में लकड़ी के साथ अन्य सामान बहकर आने से सिलसिला अभी थमा नहीं है। कुशीनगर जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की थी कि तेज बहाव वाली नदी में बह रहे सामानों के चक्कर में न जाएं। पुलिस और होमगार्ड जवानों को लगाकर ऐसे लोगों को सख्ती से रोकने के आदेश दिए गए थे ताकि किसी की जान को खतरा न हो। शुक्रवार को खड्डा व छितौनी इलाके में इस अपील का कोई असर नहीं दिखा। तटबंध के आसपास गांव के लोग नदी में कह रही लकड़ियों और अन्य सामानों को पकड़ने के लिए अब भी जान जोखिम में डाल रहे हैं।

सऊदी अरब सरकार ने 14,434 को किया गिरफ्तार और 14,905 को देश से निकाला

1,450 को अवैध रूप से देश में घुसने पर पकड़ा, सजा के साथ जुर्माना भी लगेगा

रियाद। सऊदी सरकार ने अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। सऊदी अरब ने 20 से 26 अगस्त के बीच देश के सभी इलाकों में चलाए गए जॉइंट सिक्योरिटी कैंपेन में रेजिडेंसी, लेबर और बॉर्डर सिक्योरिटी नियमों का उल्लंघन करने वाले 14,434 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं 14,905 विदेशियों को देश से बाहर निकाला गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक ये देशव्यापी कैंपेन संबंधित सिक्योरिटी अथॉरिटीज की ओर से सऊदी अरब के रेजिडेंसी, लेबर और बॉर्डर सिक्योरिटी कानूनों का उल्लंघन करने वाले लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चलाए गए। इसमें अलग-अलग मामलो में गिरफ्तारियां की गई हैं और देश निकाला गया।

कुल 14,434 उल्लंघनकताओं को गिरफ्तार किया गया। 6,976 ने रेजिडेंसी सिस्टम के नियमो का उल्लंघन करते पाए गए। 4,110 ने बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम का उल्लंघन किया। वहीं 3,348 लोगों को लेबर नियमों के उल्लंघन में पकड़ा है। सऊदी अरब की सिक्योरिटी अथॉरिटीज ने 1,450 लोगों को बॉर्डर पर अवैध रूप से देश में घुसने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया है। इनमें 41फीसदी यमनी और 58फीसदी इथियोपियाई नागरिक थे। इसके अलावा अथॉरिटीज ने 44 लोगों को गलत तरीके से बॉर्डर पार करके सऊदी अरब से अवैध रूप से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए पकड़ा।

रिपोर्ट के मुताबिक अथॉरिटीज ने 18,914 उल्लंघनकताओं को ट्रैवल डॉक्यूमेंट प्राप्त करने के लिए उनके डिप्लोमैटिक मिशनों के पास भेजा है। 2,867 नियमों का उल्लंघन करने वालों को अपनी यात्रा का रिजर्वेशन पूरा करने के लिए कहा है। 14,905 उल्लंघन करने वालों को सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया। सऊदी गृह मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि देश के बॉर्डर सिक्योरिटी नियमों के उल्लंघन में लोगों की मदद करने वालों को कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। बॉर्डर सिक्योरिटी नियमों का उल्लंघन करने वालों की मदद करना उन बड़े अपराधों में से एक माना जाता है जिनके लिए गिरफ्तारी जरूरी है। इसमें शामिल लोगों को 15 साल तक की जेल और एक मिलियन रियाल तक का जुमार्ना हो सकता है।

सऊदी अधिकारियों ने अपील की है कि वे बॉर्डर सिक्योरिटी नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों की मदद या पनाह देने में शामिल किसी भी व्यक्ति की रिपोर्ट करें। इसके लिए मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत के इलाकों और सऊदी अरब के बाकी सभी इलाकों के लिए अलग-अलग नंबर जारी किए गए हैं। सऊदी अरब हालिया महीनों में अपने रेजिडेंसी, लेबर और बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू कर रहा है। सऊदी सरकार इस पर जोर दे रही है कि देश में रहने वाले विदेशियों, नौकरी देने वालों और अन्य लोगों को यह पक्का करना चाहिए कि वे देश के कानूनों का पालन करें और बॉर्डर सिक्योरिटी नियमों का उल्लंघन ना हो।

डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी और रामबन भूस्खलन के लिहाज से बेहद संवेदनशील

नई दिल्ली। नेपाल में हाल में आई प्राकृतिक आपदा के बाद हिमालयी क्षेत्रों की संवेदनशीलता को लेकर चिंता बढ़ी है। इसी बीच जम्मू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के नए अध्ययन में जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों को भूस्खलन के लिहाज से अत्यधिक संवेदनशील बताया गया है। अध्ययन में डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी और रामबन जिलों को सबसे ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्रों में शामिल किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि यह किसी निश्चित घटना की भविष्यवाणी नहीं, बल्कि भूस्खलन की संभावना वाले क्षेत्रों की वैज्ञानिक पहचान है। शोधकताओं ने करीब 43 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का अध्ययन कर भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्र तैयार किया। अध्ययन के मुताबिक कुल क्षेत्रफल का करीब 24.4 फीसदी हिस्सा उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में है, जबकि करीब 3.6 फीसदी इलाका अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र में पाया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस मानचित्र के जरिए प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को पहले से तैयारी करने में मदद मिल सकती है।

अध्ययन में पुराने 669 भूस्खलन मामलों का भी विश्लेषण किया गया। इनमें करीब 87 फीसदी घटनाएं उन क्षेत्रों में दर्ज हुईं, जिन्हें मानचित्र में उच्च या अत्यधिक जोखिम वाले जोन में रखा गया है। इससे तैयार किए गए जोखिम मानचित्र की उपयोगिता और वैज्ञानिक विश्वसनीयता को बल मिलता है। शोधकताओं के मुताबिक भूस्खलन का सटीक समय और स्थान पहले से बताना संभव नहीं है, लेकिन संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर नुकसान को कम करने की तैयारी की जा सकती है। डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी और रामबन जैसे जिलों में तेज ढलान और कई स्थानों पर कमजोर भूगर्भीय संरचना जोखिम बढ़ाती है। इसके अलावा सड़क निर्माण के लिए पहाड़ों की कटाई, वनस्पति में कमी और अन्य मानवीय गतिविधियां भी ढलानों की स्थिरता को प्रभावित कर सकती हैं। भारी और लगातार बारिश ऐसी पहले से कमजोर ढलानों के लिए बड़े ट्रिगर का काम कर सकती है। रिसर्च टीम ने अध्ययन के लिए उपग्रह चित्रों, फील्ड सर्वे और पुराने भूस्खलन रिकॉर्ड का उपयोग किया।

वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में लगातार निगरानी, बारिश में विशेष सतर्कता, कमजोर ढलानों को स्थिर करने के उपाय और सड़क निर्माण में वैज्ञानिक मानकों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि हिमालयी क्षेत्रों में आपदाओं को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, लेकिन समय रहते जोखिम की पहचान और प्रभावी तैयारी से बड़े नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

चीन में गहराया जनसांख्यिकीय संकटः जन्म दर फिर गिरी, आबादी में रिकॉर्ड गिरावट

बीजिंग। चीन वर्तमान में एक गंभीर जनसांख्यिकीय संकट से जूझ रहा है। वर्ष 2025 में देश की जन्म दर में फिर बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। नेशनल हेल्थ कमीशन के आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार, इस साल केवल 79.2 लाख बच्चों का जन्म हुआ। यह चीन के लिए बड़ा झटका है, खासकर इसलिए क्योंकि 2024 में मामूली वृद्धि के बाद यह गिरावट आई है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सरकार जन्म दर बढ़ाने के लिए कई प्रोत्साहन कार्यक्रम चला रही है, लेकिन जमीन पर इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 के अंत में चीन की कुल आबादी 140.489 करोड़ थी। प्रति 1,000 लोगों पर जन्म दर 5.63 रही, जबकि इस अवधि में 1.131 करोड़ मौतें दर्ज की गईं, जिससे मृत्यु दर 8.04 प्रति 1,000 लोगों पर पहुंच गई। परिणामस्वरूप, पिछले साल जनसंख्या वृद्धि की प्राकृतिक दर गिरकर प्रति 1,000 लोगों पर -2.41 हो गई, जो देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण नकारात्मक आंकड़ा है।

खामोशी के बाद लारक द्वीप पर अमेरिका ने दागीं मिसाइलें, ईरान ने भी दिया जवाब

तेहरान। सोमवार तड़के ईरान और अमेरिका के बीच करीब एक महीने की खामोशी के बाद फिर सैन्य टकराव तेज हो गया। अमेरिका ने ईरान के रणनीतिक लारक द्वीप पर दो मिसाइलें दागीं, जिसके बाद ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने जवाबी कार्रवाई कर जॉर्डन में मौजूद दो अमेरिकी एयरबेस- किंग हुसैन और मुवाफ्फक सल्ती एयर बेस को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने की बात कही है। जॉर्डन की सेना ने कहा कि उसके एयर डिफेंस ने देश के हवाई क्षेत्र में घुसी 8 मिसाइलों को इंटरसेंप्ट कर दिया है।

रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन ईरान के ठीक सामने नहीं है, लेकिन अमेरिका के लिए यह मिडिल ईस्ट में एक बेहद अहम फॉरवर्ड ऑपरेटिंग और लॉजिस्टिक्स हब बन चुका है। 2021 के अमेरिका-जॉर्डन रक्षा समझौते के तहत अमेरिकी सेना को जॉर्डन की कई सैन्य फैसिलिटी तक पहुंच मिली है। इनमें एयरबेस भी शामिल हैं। खासकर मुवाफ्फक सल्ती एयर बेस पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों का बड़ा केंद्र बना है। जॉर्डन में मौजूद बेस का इस्तेमाल अमेरिकी लड़ाकू विमानों, ड्रोन, एयर डिफेंस और सैन्य लॉजिस्टिक्स के लिए किया जाता है यानी ईरान अगर अमेरिका के क्षेत्रीय सैन्य नेटवर्क पर दबाव बनाना चाहता है, तो जॉर्डन उसके लिए अहम निशाना है।

एफ-35अ अमेरिका के सबसे एडवांस्ड स्टील्थ लड़ाकू विमानों में से एक है। इसकी खासियत सिर्फ बम गिराने की क्षमता नहीं, बल्कि दुश्मन की एयर डिफेंस व्यवस्था से बचते हुए लंबी दूरी तक ऑपरेशन करने और सेंसर के जरिए युद्धक्षेत्र की जानकारी जुटाने की क्षमता भी है। जुलाई में अमेरिकी वायुसेना ने बताया था कि 421एसटी एक्सपीडीशियनरी फाइटर स्वाड्रन के एफ-35ए विमान भेजे गए हैं। अमेरिकी वायुसेना की जारी तस्वीरों को विश्लेषकों ने मुवाफ्फक सल्ती एयर बेस से जोड़ा था। इसलिए ईरान के लिए यह एयरबेस महज रनवे नहीं, बल्कि अमेरिकी एयर ऑपरेशन की एक अहम कड़ी है।

ईरान ने जिस दूसरे ठिकाने को निशाना बनाने का दावा किया है, वह किंग हुसैन एयर बेस है। आईआरजीसी के मुताबिक दोनों ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया गया और तकनीकी, रखरखाव सुविधाओं तथा लड़ाकू विमानों की तैनाती वाले क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। जॉर्डन का असली महत्व उसकी लोकेशन में छिपा है। यह देश सीरिया, इराक, इजराइल और सऊदी अरब के बीच स्थित है यानी अमेरिकी सेना के लिए यह लेवांत, इराक और आसपास के इलाकों तक पहुंच बनाने वाला बेहद अहम स्थान है। अमेरिका के खाड़ी के दूसरे देशों में भी बेस हैं, लेकिन वहां कई बार वह ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता के लिहाज से अपेक्षाकृत सीधे खतरे में आते हैं।

अमेरिका का दावा था कि आईआरजीसी रॉकेट दागने की तैयारी कर रहा था जिनका इस्तेमाल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में समुद्री माइंस बिछाने के लिए किया जा सकता था। होर्मुज दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्गों में से एक है। यहां जहाजों की आवाजाही में बड़ा व्यवधान तेल और गैस की वैश्विक सप्लाई को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अमेरिका का तर्क है कि लारक पर हमला समुद्री रास्ते को खुला रखने की कार्रवाई थी। ईरान ने इसे अपने खिलाफ सीधा हमला माना और अब उसने अमेरिका के क्षेत्रीय सैन्य नेटवर्क पर जवाबी हमला कर संदेश दे दिया है कि वह पीछे हटने वाला नहीं है।

अटैक के बाद ईरान ने जॉर्डन में दागीं मिसाइलें, ट्रंप बोले-सैनिकों के लिए करें दुआ

वाशिंगटन। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ये हमला अमेरिका की ओर से ईरान के लारक द्वीप पर किए गए हमले के बाद किया गया। इसे लेकर ईरान ने दावा किया है कि कई ईरानी लड़ाके और नागरिक मारे गए या घायल हुए हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हो रहे हमलों को अमेरिका बेहद गंभीरता से ले रहा है। अमेरिकी सैनिक आने वाले मिसाइल हमलों और अन्य खतरों को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके मुताबिक अब जमीन पर मौजूद अमेरिकी सैनिकों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एयर डिफेंस संभाल रहे सैनिकों पर भरोसा जताया है। ट्रंप ने हमले के बाद अमेरिकी जवानों के लिए दुआ करने की अपील की है।

सैन्य कार्रवाई के साथ ही अमेरिका आर्थिक दबाव भी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि प्रशासन इस सप्ताह ईरान से जुड़े एक और बैंक पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। पिछले हफ्ते अमेरिका ने ईरान सरकार के साथ कारोबार करने के आरोप में बैंक मिस्र की यूएई गतिविधियों को अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था से काट दिया था। बेसेंट ने यह भी संकेत दिया कि चीन की ओर से ईरान से लगातार खरीदारी किए जाने के मुद्दे पर भी प्रतिबंधों समेत सभी विकल्प खुले हैं। अब अमेरिका-ईरान के बीच का युद्ध आर्थिक से लेकर समुद्री मोर्चे पर भी बढ़ गया है।

गाजा, यरूशलम और यूक्रेन ही नहीं बेलग्रेड शहर ने भी झेले 115 युद्ध, 44 बार हुआ तबाह

बेलग्रेड। अगर आज गाजा, यरूशलम और यूक्रेन बारूद के धुएं में अपनी सांसें गिन रहे हैं, तो यूरोप के केंद्र में एक ऐसा शहर बसा है जिसने इन सबसे कहीं ज्यादा दर्द झेला है। एक ऐसा शहर जो 115 से ज्यादा युद्धों का गवाह बना और जिसे 44 बार तबाही झेलनी पड़ी, लेकिन हर बार अपनी ही राख से उठकर फिर खड़ा हो गया। जी यह शहर है सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह शहर दो नदियों के संगम पर बसा है- सावा और डैन्यूब। इन दो महान नदियों के संगम पर बसा यह शहर अपनी मातृभाषा में बेओग्राद यानी सफेद शहर कहलाता है, लेकिन इसका इतिहास सफेद रंगों से ज्यादा खून के लाल रंग से लिखा गया है। करीब 10,000 साल पुरानी मानव सभ्यता के अवशेष समेटे बेलग्रेड की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। इसकी रणनीतिक स्थिति। पूर्व और पश्चिम के चौराहे पर बसे होने के कारण यह हर साम्राज्य की पहली पसंद रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईसा पूर्व चौथी सदी में केल्ट्स द्वारा बसाए जाने से लेकर रोम के सिंगिदुनम तक, बेलग्रेड पर हर किसी की नजर रही है। 5वीं सदी में अत्तिला द हुन ने इसे तबाह किया, फिर यह गॉथ, बाइजैन्टाइन, फ्रैंक्स और बुल्गारियाई शासकों के हाथों में चलर गया।

इस्तांबुल में स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल एंड डिफेंस कमेटी की पहली बैठक

अंकारा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के तहत गठित स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल एंड डिफेंस कमेटी की पहली बैठक में शामिल होने के लिए तुर्की पहुंच गए हैं। सोमवार को इस्तांबुल में होने वाली इस बैठक को तीनों देशों के बीच नए रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। बैठक के आधिकारिक एजेंडे का अभी खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन समझौते को लागू करने और इसके दायरे को आगे बढ़ाने पर चर्चा होने की संभावना है।

पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने 7 अगस्त को मक्का में मज्दा पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के तहत किसी एक सदस्य देश पर होने वाले हमले को तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। समझौते में सैन्य सहयोग को मजबूत करने और साझा सुरक्षा हितों पर समन्वय बढ़ाने की बात कही गई है। इसके अलावा भविष्य में दूसरे देशों के संभावित जुड़ाव को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज है।

तीनों देशों की अलग-अलग ताकत मक्का समझौते को तीनों देशों की अलग-अलग क्षमताओं को एक साझा रणनीतिक ढांचे में लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तुर्की के पास तेजी से विकसित हो रहा रक्षा तकनीक और सैन्य उद्योग है, सऊदी अरब के पास मजबूत वित्तीय संसाधन हैं, जबकि पाकिस्तान इस साझेदारी में अपनी सैन्य क्षमता और रक्षा क्षेत्र का अनुभव उपलब्ध करा सकता है। इस गठजोड़ से पाकिस्तान को विशेष तौर पर तुर्की के साथ रक्षा उत्पादन और सैन्य तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। इस्लामाबाद संयुक्त रूप से सैन्य उपकरणों के निर्माण, आधुनिक रक्षा प्रणालियों के विकास और रक्षा उद्योग की क्षमता बढ़ाने पर जोर दे सकता है।

सऊदी फंडिंग से मजबूत हो सकता है पाकिस्तान का रक्षा आधार

पाकिस्तान के लिए इस समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू सऊदी अरब के साथ रणनीतिक और वित्तीय सहयोग भी है। माना जा रहा है कि रियाद से मिलने वाली संभावित वित्तीय सहायता पाकिस्तान की रक्षा महत्वाकांक्षाओं को आर्थिक आधार दे सकती है। वहीं, तुर्की के साथ तकनीकी सहयोग से पाकिस्तान अपनी घरेलू रक्षा निर्माण क्षमता को विस्तार देने की कोशिश कर सकता है। इस्तांबुल में होने वाली पहली समिति बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे मक्का समझौते को कागज से आगे ले जाकर व्यावहारिक रक्षा सहयोग में बदलने की दिशा तय हो सकती है। पाकिस्तान इस मंच के जरिए दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया में अपनी रणनीतिक भूमिका बढ़ाने के अवसर तलाश सकता है।

भारत में मार्च 2027 से सभी संस्थाओं को आईएसटी का पालन करना अनिवार्य होगा

नियमों का उल्लंघन करने पर एक्ट के तहत जुर्माना भी लगाया जाएगा

नई दिल्ली। अगले साल मार्च 2027 से भारत में सभी संस्थाओं को कानूनी, कमर्शियल, डिजिटल और प्रशासनिक कामों के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम (आईएसटी) का इस्तेमाल करना होगा।

सरकार ने इस संबंध में लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स, 2026 का ऐलान किया है। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत घोषित ये नियम गजट में पब्लिश होने के 180 दिन बाद लागू होंगे, जिससे मार्च 2027 के आसपास से आईएसटी अनिवार्य हो जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर एक्ट के तहत जुमार्ना लगाया जाएगा। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के तहत जब तक खास तौर पर छूट न दी गई हो, सभी कानूनी, प्रशासनिक और आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स के लिए भारतीय मानक समय (आईएसटी) अनिवार्य टाइम रेफरेंस होगा। यह कमर्शियल गतिविधियों, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कानूनी कॉन्ट्रैक्ट्स और फाइनेंशियल ऑपरेशन्स में भी आईएसटी को स्टैंडर्ड टाइम रेफरेंस बनाता है।

संस्थाओं को आधिकारिक कामों के लिए आईएसटी के अलावा किसी अन्य टाइम रेफरेंस का इस्तेमाल, डिस्प्ले या रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं होगी, सिवाय उन मामलों के जहां विदेशी टाइम जोन स्पष्ट रूप से बताए गए

हों। या फिर जहां वैज्ञानिक रिसर्च, नेविगेशन या खगोल विज्ञान के लिए वैकल्पिक टाइम सोर्स की इजाजत हो। ये नियम इसलिए अहम हैं क्योंकि आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर माइक्रोसेकंड-लेवल की टाइमिंग सटीकता पर निर्भर करता है। पेमेंट सिस्टम, स्टॉक एक्सचेंज, टेलीकॉम नेटवर्क, 5जी सर्विस, डिजिटल नेविगेशन, पावर ग्रिड और डेटा सेंटर को ट्रांजैक्शन प्रमाणित करने में अहम रोल ऐसे ऑपरेशन्स में तालमेल बिठाने और नेटवर्क की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सिंक्रोनाइज्ड घड़ियों की जरूरत होती है।

नियमों के तहत नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी भारत के प्राइमरी टाइम स्केल को बनाए रखना जारी रखेगी। इससे आईएसटी लिया जाता है, जबकि रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरीज, इसरो का नेवेआईसी और अन्य अधिकृत टाइमिंग सोर्स आधिकारिक समय का प्रसार करेंगे। इन नियमों की एक और बड़ी विशेषता साइबर रेजिलिएंस पर ध्यान देना है। संगठनों को उचित टाइम-सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम लगाने होंगे, नेटवर्क को स्पूफिंग, जैमिंग और साइबर हमलों से बचाना होगा, कई अधिकृत टाइमिंग सोर्स को इंटीग्रेट करना होगा। बिना रुकावट के काम सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक व्यवस्था बनाए रखनी होगी, जिसमें जरूरत पड़ने पर एटॉमिक घड़ियां भी शामिल हैं।

ताजा खबर

संक्षिप्त

दुर्ग से बिलासपुर तक जल्द दौड़ेगी ट्रेनें 130 की स्पीड से

रायपुर। रायपुर रेल मंडल रेलवे ट्रैक के किनारे सेफ्टी फेंसिंग का कार्य तेजी से कर रहा है। बिलासपुर-दुर्ग सेक्शन में कुल 273 किमी के दायरे में सेफ्टी फेंसिंग का प्रावधान किया गया है, जिसमें से अब तक 165.9 किमी (166 किलोमीटर) में कार्य पूर्ण किया जा चुका है। रेलवे ट्रैक के आसपास आम लोगों, पालतू पशुओं और जंगली जानवरों के अनधिकृत प्रवेश को रोकने में सेफ्टी फेंसिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके माध्यम से पैदल यात्रियों को अनजाने में रेलवे ट्रैक पर प्रवेश करने से रोकने के साथ-साथ मवेशियों एवं जंगली जानवरों के ट्रैक पर आने की संभावना को भी कम किया जाता है। इससे ट्रैक पर होने वाली दुर्घटनाओं, ट्रेन संचालन में व्यवधान तथा रेलवे परिसंपत्तियों को होने वाले नुकसान के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। साथ ही 130 किमी प्रति घंटे तक यात्री ट्रेनों की गति बढ़ाने की दिशा में भी सेफ्टी फेंसिंग महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सेफ्टी फेंसिंग के माध्यम से रेलवे ट्रैक के आसपास एक सुरक्षित एवं नियंत्रित कॉरिडोर तैयार होता है, जिससे इस प्रकार के जोखिमों को कम किया जा सकता है। इससे सुरक्षित, तेज एवं सुचारू रेल परिचालन को बढ़ावा मिलता है तथा भविष्य में ट्रेनों की गति बढ़ाने से संबंधित योजनाओं को भी मजबूती मिलती है। रायपुर रेल मंडल द्वारा सेफ्टी फेंसिंग के कार्य को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे रेल यात्रियों, आम जनता तथा रेल परिचालन की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।

रायपुर में 3 सितंबर को होगा 'गुरु वंदन उत्सव

रायपुर. शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर 3 सितंबर को शहीद स्मारक भवन में 'तिरंगा शक्ति फेस्ट 2026 गुरु वंदन उत्सव' का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया जाएगा। रायपुर जिला प्रशासन, नगर निगम संस्कृति विभाग, कला केंद्र रायपुर और स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से होने वाले इस आयोजन में शिक्षक और छात्र शामिल होंगे। पहले यह कार्यक्रम 5 सितंबर को प्रस्तावित था, जिसे संशोधित कर 3 सितंबर किया गया है। आयोजन में दो आयु वर्गों में गायन और नृत्य प्रतियोगिताएं होंगी। जूनियर वर्ग में 5 से 15 साल और सीनियर वर्ग में 15 से 70 साल तक के प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे। प्रतियोगिता के जरिए अलग-अलग आयु वर्ग के प्रतिभागियों को अपनी गायन और नृत्य प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। प्रतियोगिता के लिए ऑडिशन 30 अगस्त को टाउनहाल रायपुर में होंगे। ऑडिशन का समय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक रखा गया है। इच्छुक प्रतिभागी निर्धारित समय के दौरान पहुंचकर ऑडिशन दे सकेंगे। आयोजन का उद्देश्य बच्चों, युवाओं और अन्य आयु वर्ग के प्रतिभागियों को अपनी कला दिखाने के लिए मंच देना है। इसके साथ ही गायन और नृत्य में रुचि रखने वाले प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा को और बेहतर करने का अवसर मिलेगा। ग्रैंड फिनाले में चयनित प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति देंगे।

राज्य महिला आयोग का नारी शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन सम्पन्न

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अलग-अलग क्षेत्रों की महिलाओं को किया सम्मानित

रायपुर. छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने आज नारी शक्ति सम्मान समारोह' आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चिकित्सा, शिक्षा, खेल, पत्रकारिता, साइबर सुरक्षा, कला-संस्कृति, कृषि, उद्यमिता और सामाजिक सेवा समेत अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। राज्य महिला आयोग के 25 साल पूरे होने पर महिला आयोग की नई अध्यक्ष डॉ. ममता साहू की अध्यक्षता में कार्यक्रम

आयोजित किया गया था, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय के साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी मौजूद रहे।

13.85 लाख 'लखपति दीदी', 481 महतारी सदन बन रहे

मुख्यमंत्री साय बोले: महिलाओं को सिर्फ योजनाओं का लाभार्थी नहीं बनाना

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार का फोकस महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को योजनाओं का लाभ लेने तक सीमित रखने के बजाय उन्हें रोजगार, उद्यम और आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने की जरूरत है।उन्होंने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत 68 लाख से ज्यादा महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। अब तक योजना की 31 किस्तें जारी हो चुकी हैं।

साय ने बताया कि प्रदेश में 13 लाख 85 हजार से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं खेती, वनोपज और छोटे कारोबार के साथ तकनीकी कामों में भी आगे बढ़ रही हैं। महिला समूहों की गतिविधियों के लिए प्रदेश में 481 महतारी सदन बनाए जा रहे हैं। वहीं 'मेरी बेटी, मेरा अभिमान' के तहत 6,671 बालिका शौचालयों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।मुख्यमंत्री ने महिला आयोग की नई अध्यक्ष डॉ. ममता साहू को बधाई देते हुए कहा कि आयोग को सिर्फ शिकायतों के निपटारे तक सीमित नहीं रहना चाहिए। गांवों, कस्बों और दूरदराज के इलाकों में जाकर महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी भी देनी चाहिए।

साय ने महिलाओं के नाम जमीन और संपत्ति के पंजीयन को भी महिला सशक्तिकरण से जोड़ा। उनके मुताबिक, महिला के नाम संपत्ति होने से उसका आर्थिक आधार मजबूत होता है और परिवार के फैसलों में उसकी भूमिका बढ़ती है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल सरकारी योजनाओं से नहीं होगा। इसके लिए बेटियों की शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार और उद्यमिता के अवसर बढ़ाने के साथ समाज की सोच में भी बदलाव जरूरी है।

कहा- 'नशामुक्त युवा, विकसित भारत' के संकल्प में सभी की भागीदारी जरूरी

सीएम ने सुनी मन की बात

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित निरंजन धर्मशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की 137वीं कड़ी का श्रवण किया. मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 'मन की बात' केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का देश के 140 करोड़ नागरिकों से आत्मीय संवाद का सशक्त माध्यम है. इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री देश के अलग-अलग हिस्सों में हो रहे नवाचारों, प्रेरक प्रयासों और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले लोगों की उपलब्धियों को पूरे देश के सामने रखते हैं. मुख्यमंत्री साय ने कहा कि देशवासियों को प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को प्रसारित होने वाले 'मन की बात' कार्यक्रम की प्रतीक्षा रहती है. प्रधानमंत्री इसमें ऐसे अनेक विषयों और व्यक्तित्वों का उल्लेख करते हैं, जिनके बारे में सामान्यत: देश के लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती. इससे जहां अच्छे कार्य करने वाले लोगों का उत्साह बढ़ता है, वहीं उनके प्रयास लाखों देशवासियों के लिए प्रेरणा बनते हैं. उन्होंने कहा कि हमारे देश के दूरस्थ गांवों और छोटे-छोटे क्षेत्रों में अनेक लोग बिना किसी प्रचार और स्वार्थ के समाज तथा राष्ट्रहित में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं. कोई पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे रहा है, कोई स्वच्छता के लिए कार्य कर रहा है, तो कोई स्थानीय संसाधनों के माध्यम से नवाचार कर अपने क्षेत्र में बदलाव ला रहा है. प्रधानमंत्री मोदी 'मन की बात' के माध्यम से ऐसे सामान्य लोगों के असाधारण कार्यों को राष्ट्रीय पहचान देते हैं. इससे देश में सकारात्मकता और जनभागीदारी की भावना मजबूत होती है तथा दूसरे लोगों को भी कुछ नया और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है.

'नशामुक्त युवा, विकसित भारत' के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज 'नशामुक्त युवा, विकसित भारत' के संकल्प को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिया. युवा शक्ति विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी ताकत है. ऐसे में युवाओं को नशे से दूर रखना परिवार, समाज और राष्ट्र सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा केवल किसी एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित नहीं करता, बल्कि उसके दुष्प्रभाव पूरे परिवार और समाज को झेलने पड़ते हैं. स्वस्थ, समर्थ और ऊर्जावान युवा पीढ़ी ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकती है. उन्होंने प्रदेशवासियों से नशामुक्ति के प्रयासों में सक्रिय भागीदारी निभाने और युवाओं को स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवन के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया.

हर घर तिरंगा' में दिखा देशवासियों का राष्ट्रप्रेम

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' में 'हर घर तिरंगा' अभियान के प्रति देशवासियों के अभूतपूर्व उत्साह का भी उल्लेख किया. अभियान के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक देशवासियों ने तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड की. यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि राष्ट्रध्वज के प्रति देशवासियों के सम्मान, गौरव और गहरे भावनात्मक जुड़ाव की अभिव्यक्ति है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर 'हर घर तिरंगा' आज जन-जन का अभियान बन चुका है. ऐसे अभियान राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने के साथ प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका और कर्तव्यों का स्मरण कराते हैं.

पीएम स्वनिधि से मातृशक्ति को मिल रही आर्थिक संबल

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की भी चर्चा की. रेहड़ी-पटरी और छोटे व्यवसायों से जुड़ी महिलाओं को योजना के माध्यम से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है. उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में लगभग 46 प्रतिशत महिलाएं हैं और देशभर में करीब 35 लाख महिलाएं इससे जुड़कर अपने छोटे व्यवसायों को नई गति दे रही हैं.

11 को इंद्रावती भवन के सामने अनियमित कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन

रायपुर। राज्य सरकार द्वारा मोदी की गारंटी पूरी नहीं करने, नियमितीकरण करने और आउटसोर्सिंग बंद करने की मांग को लेकर अनियमित कर्मचारी एक बार फिर आंदोलन पर उतर रहे हैं। इसकी शुरुआत 11 सितम्बर को इंद्रावती भवन नवा रायपुर के समक्ष सांकेतिक प्रदर्शन से होगी।

छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल प्रसाद साहू एवं एक मांग-एक मंच अभियान के संयोजक करन सिंह अटेरिया ने कहा, कि अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण करने एवं आउट सोर्सिंग बंद करने जैसे विषयों पर सरकार वादे के मुताबिक संवेदनशील नहीं है। न्यूनतम वेतन में पिछले 9 साल और संविदा वेतन में पिछले 3 साल से कोई वृद्धि नहीं की गई है। इससे लाखों अनियमित कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा, की मोदी की गारंटी को भी सरकार पूरा नहीं कर रही है। आर्थिक शोषण के खिलाफ क्रमिक आंदोलन के क्रम में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर नियमित, अनियमित एवं सेवानिवृत कर्मचारी और अधिकारी 11 सितम्बर को भोजनावकाश में इंद्रावती भवन के सामने सांकेतिक प्रदर्शन कर नोडल अधिकारी इंद्रावती भवन को मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौपेंगे।

बता दें, कि अनियमित कर्मचारी संघ की प्रमुख मांगों में, जनवरी 2026 की स्थिति से कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता जारी करने के साथ 86 महीनों का एरियर्स भी दिया जाए। अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण, सेवा से निकाले गए कर्मचारियों की बहाली, न्यून मानदेय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालिक करने तथा अउटसोर्सिंग या ठेका माध्यम से नियोजन सिस्टम बंद किया जाए।

उच्च शिक्षा मिशन शुरू, 36 कॉलेज बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

रायपुर। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक और त्वरित सुधार लाने के लिए छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन शुरू किया गया है। इसके तहत महाविद्यालयों का चयन कर प्रतिवर्ष उनके ढांचागत और शैक्षणिक उन्नयन के लिए विशेष राशि स्वीकृत की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप, राज्य के हर जिले में बहुसंकायी और अनुसंधान-केंद्रित शिक्षण संस्थानों की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। जिन महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 3000 से अधिक है उन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। ये 36 महाविद्यालय राज्य में शोध, नवाचार और उच्चस्तरीय अध्यापन के प्रमुख केंद्र बनकर

उभरें। कालेजों में स्ववित्तीय पाठ्यक्रम नीति लागू की जा रही है। इसके तहत स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रोजगारपरक और तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स, सेरीकल्चर (रेशम कीट पालन), फिशरीज और टसर टेक्नोलॉजी जैसे विषयों की पढ़ाई शुरू की जा रही है।?आधुनिक तकनीक व उद्यमिता के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस , साइबर सिक्योरिटी, वेब डिजाइनिंग, फूड प्रोसेसिंग, मशरूम कल्टीवेशन, फ्लोरीकल्चर और हर्बल कल्टीवेशन जैसे विषयों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। इन सभी के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ-साथ राज्य के कौशल विकास व तकनीकी विभागों के साथ रूश किए हैं, ताकि युवाओं को सीधे उद्योग और व्यावहारिक अनुभव से जोड़ा जा सके। दूरस्थ आदिवासी और वनांचल क्षेत्रों में नवीन महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। इसके साथ ही औद्योगिक प्रतिष्ठानों की मदद से इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के द्वार खोले गए हैं।

शैक्षणिक क्षेत्र को और सशक्त बनाने के लिए चार वर्षीय बी.एड. और बी.पी.एड. जैसे एकीकृत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन भी शुरू किया जा रहा है। इसी तरह से उद्योग जगत और व्यावहारिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में महाविद्यालयों से जोडने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही, उच्च शिक्षा विभाग में अध्यापन व्यवस्था को नई ऊर्जा देने के लिए शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक के 595 पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया को तेजी से पूर्ण किया जा रहा है।

एनआईटी रायपुर में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आगाज

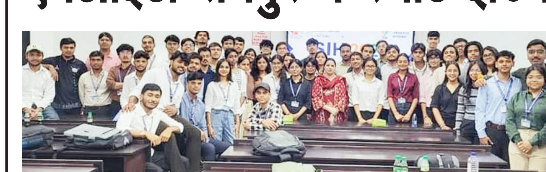

135 टीमों ने कराया रजिस्ट्रेशन; 80 शॉर्टलिस्ट

रायपुर. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर में शनिवार, 29 अगस्त 2026 को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2026 के लिए %इंटरनल हैकाथॉन% का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के विभिन्न शैक्षणिक विभागों के छात्रों ने उत्साह के साथ भाग लिया और वास्तविक दुनिया की जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित अपने अभिनव विचार प्रस्तुत किए।

135 टीमों ने कराया पंजीकरण, 80 को मिला मौका

इस इंटरनल हैकाथॉन को छात्र समुदाय से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। कुल 135 टीमों ने अपना पंजीकरण कराया। स्क्रीनिंग के बाद संस्थान स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 80 टीमों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इन टीमों ने विशेषज्ञों के मूल्यांकन पैनल के सामने अपने विचार, तकनीकी दृष्टिकोण और कार्यशील प्रोटोटाइप प्रस्तुत किए।

10 पैनलों ने किया टीमों के समाधान का मूल्यांकन

शॉर्टलिस्ट की गई टीमों को 10 समानांतर मूल्यांकन पैनलों में विभाजित किया गया। इनमें एनआईटी रायपुर के संकाय सदस्यों के साथ बाहरी विषय-विशेषज्ञ और उद्योग जगत के विशेषज्ञ शामिल थे। इस व्यवस्था के जरिए छात्रों को अनुभवी विशेषज्ञों के सामने अपने समाधान प्रस्तुत करने और तकनीकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने का अवसर मिला। मूल्यांकन प्रक्रिया कई प्रमुख मानकों के आधार पर की गई। इनमें समस्या की समझ और प्रासंगिकता, नवाचार और नवीनता, तकनीकी दृष्टिकोण और आर्किटेक्चर, प्रोटोटाइप का क्रियान्वयन, व्यावहारिकता, प्रभावशीलता, स्केलेबिलिटी और प्रस्तुतीकरण कौशल शामिल थे। इस आयोजन ने छात्रों के बीच अंतर-विषयक सीखने, टीमवर्क और तकनीक-केंद्रित समस्या निवारण को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक मंच के रूप में काम किया। तकनीकी प्रतिभा के प्रदर्शन के अलावा, इंटरनल हैकाथॉन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2026 के लिए आधिकारिक संस्थान-स्तरीय चयन प्रक्रिया का चरण भी है।

आवेदन की अंतिम तारीख 15 सितंबर चयन राज्य पर्यटन विभाग और निर्णायक समिति के मानकों के आधार पर होगा

छत्तीसगढ़ पर्यटन को मिलेगा सम्मान 10 श्रेणियों में दिए जाएंगे विश्व पर्यटन दिवस पुरस्कार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पर्यटन क्षेत्र को नई पहचान देने, पर्यटन से जुड़े उद्यमियों, संस्थाओं एवं व्यक्तियों के उत्कृष्ट कार्यों को प्रोत्साहित करने तथा राज्य के पर्यटन स्थलों के विकास, संवर्धन एवं प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा 'विश्व पर्यटन दिवस पुरस्कार-2026' प्रदान किए जाएंगे। इस पुरस्कार योजना के तहत पर्यटन क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले होटल, पंजीकृत टूर ऑपरेटर, जिले, पर्यटन स्टार्टअप, रिसॉर्ट, पर्यटक सूचना केंद्र, होमस्टे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इको-टूरिज्म साइट और एडवेंचर टूरिज्म संचालकों को सम्मानित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत कुल 10 श्रेणियों में एक-एक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक विजेता को ?11 हजार की पुरस्कार राशि एवं मेमेंटो प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। पर्यटन की पूरी श्रृंखला को प्रोत्साहित करने पर जोर 'विश्व पर्यटन दिवस पुरस्कार-2026' की खासियत यह है कि इसमें पर्यटन को केवल पर्यटन स्थलों तक सीमित न रखते हुए उससे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों को भी सम्मान के दायरे में शामिल किया गया है। आतिथ्य, पर्यटन संचालन, जिला पर्यटन प्रबंधन, उद्यमिता, रिसॉर्ट सेवाएं, पर्यटक सहायता, होमस्टे, डिजिटल प्रचार, पर्यावरण संरक्षण और साहसिक पर्यटन जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार की 10 श्रेणियां हैं— 1. सर्वश्रेष्ठ होटल 2. सर्वश्रेष्ठ पंजीकृत टूर ऑपरेटर 3. सर्वश्रेष्ठ जिला टूरिज्म प्रमोशन अवॉर्ड 4. सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्टार्टअप/उद्यमिता पुरस्कार 5. CTB Star Performer – सर्वश्रेष्ठ रिसॉर्ट 6. CTB Star Performer – पर्यटक सूचना केंद्र 7. सर्वश्रेष्ठ होमस्टे 8. सर्वश्रेष्ठ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 9. सर्वश्रेष्ठ इको टूरिज्म साइट अवॉर्ड 10. सर्वश्रेष्ठ एडवेंचर टूरिज्म अवॉर्ड बेहतर सेवाओं और नवाचार को मिलेगा सम्मान, सर्वश्रेष्ठ होटल श्रेणी में राज्य के आतिथ्य क्षेत्र में प्रभावशाली सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले पर्यटन उद्यम को सम्मानित किया जाएगा। इसमें स्ल्रुष्टश्च सुविधाओं, पिछले वित्तीय वर्ष के वित्तीय प्रदर्शन, वार्षिक कारोबार और आयोजित कार्यक्रमों की संख्या जैसे मानकों को आधार बनाया जाएगा। पर्यटन प्रचार, सतत पर्यटन, ष्टस्क्र गतिविधियों और रोजगार सृजन में योगदान को भी मूल्यांकन में महत्व दिया जाएगा। इसी तरह सर्वश्रेष्ठ पंजीकृत टूर ऑपरेटर का चयन आवास, परिवहन, दर्शनीय स्थलों की यात्रा, मनोरंजन और अन्य पर्यटन गतिविधियों के प्रभावी संचालन तथा छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों के आधार पर किया जाएगा। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी, इटिनरेरी एवं प्रचार सामग्री के माध्यम से पर्यटन का प्रचार तथा वेबसाइट और सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग को भी मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा। पर्यटन विकास में

उत्कृष्ट जिले को भी मिलेगा सम्मान 'सर्वश्रेष्ठ जिला टूरिज्म प्रमोशन अवॉर्ड' के तहत उस जिले का चयन किया जाएगा, जिसने पर्यटन के व्यापक विकास, संवर्धन, गंतव्य प्रबंधन तथा घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने की दिशा में बेहतर कार्य किया हो। पर्यटन स्थलों की स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, डस्टबिन की उपलब्धता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, हरित उपाय, प्रकृति आधारित गतिविधियां, कृषि एवं ग्रामीण जीवनशैली, संस्कृति, मत्स्य पालन, पर्यटकों के लिए विशिष्ट अनुभव और पर्यटन के माध्यम से रोजगार सृजन जैसे पहलुओं को भी मूल्यांकन में शामिल किया गया है। युवा उद्यमियों और पर्यटन स्टार्टअप को मिलेगा मंच पर्यटन क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्टार्टअप/उद्यमिता पुरस्कार रखा गया है। इसके माध्यम से ऐसे स्टार्टअप और व्यक्तिगत उद्यमियों को पहचान एवं प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिन्होंने नवाचार एवं अनुकरणीय गतिविधियों के जरिए छत्तीसगढ़ के पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा देने का कार्य किया है। यह पुरस्कार पर्यटन क्षेत्र में नए विचारों, तकनीक, सेवाओं एवं व्यावसायिक मॉडलों के माध्यम से पर्यटन को अधिक आकर्षक, सुविधाजनक एवं प्रतिस्पर्धी बनाने वाले उद्यमियों के प्रयासों को प्रोत्साहित करेगा। रिसॉर्ट और पर्यटक सूचना केंद्रों की सेवाओं को भी पहचान ष्टञ्जक्रस्लुड्डह्-क्कद्धह्द्धश्हद्धद्गह्- की दो श्रेणियों में पर्यटन बोर्ड की प्रीमियम एवं बजट श्रेणी की इकाइयों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले रिसॉर्ट तथा उल्लेखनीय बुकिंग उपलब्ध कराने वाले पर्यटक सूचना केंद्रों को सम्मानित किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ रिसॉर्ट के चयन में टर्नओवर, लाभप्रदता और अधिभोग प्रतिशत जैसे मानकों को आधार बनाया जाएगा।

वहीं पर्यटक सूचना केंद्रों का मूल्यांकन पूरे वर्ष पर्यटकों के लिए बुकिंग उपलब्ध कराने में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। इन पुरस्कारों के माध्यम से पर्यटन बोर्ड की इकाइयों में बेहतर सेवा, ग्राहक संतुष्टि, प्रभावी संचालन तथा पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा। होमस्टे से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वालों का सम्मान सर्वश्रेष्ठ होमस्टे श्रेणी में घरेलू पर्यटन से अर्जित राजस्व, वार्षिक वृद्धि दर, बुकिंग की संख्या और घरेलू पर्यटकों की संख्या जैसे मानकों के आधार पर चयन किया जाएगा। पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाएं, ग्राहक समीक्षा, शिकायत निवारण प्रणाली, दिव्यांग पर्यटकों के लिए सुविधाएं तथा होमस्टे की विशिष्ट अवधारणा को भी मूल्यांकन में महत्व दिया जाएगा। होमस्टे के माध्यम से स्थानीय समुदायों को पर्यटन से जोड़ने, स्थानीय उत्पादों एवं व्यंजनों को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं आय के अवसर सृजित करने वाले प्रयासों को भी विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। डिजिटल दुनिया में छत्तीसगढ़ पर्यटन की ब्रांडिंग करने वालों को पुरस्कार सोशल मीडिया की बढ़ती भूमिका को देखते हुए सर्वश्रेष्ठ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रेणी भी शामिल की गई है। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों पर आधारित रील्स, वीडियो और अन्य डिजिटल कंटेंट के माध्यम से राज्य के पर्यटन को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को इस श्रेणी में सम्मानित किया जाएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर कंटेंट की पहुंच, पिछले तीन वर्षों के प्रदर्शन तथा उपलब्ध होने पर कारोबार संबंधी विवरण को भी मूल्यांकन का हिस्सा बनाया गया है। इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत, जनजातीय जीवन, ऐतिहासिक स्थलों, वन्यजीव, साहसिक गतिविधियों और अन्य पर्यटन आकर्षणों को डिजिटल माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रचारित करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को प्रोत्साहन मिलेगा।

अब फ्रेंचाइजी क्रिकेट में खेलना ही लक्ष्य : क्लासेन

डर्बन। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व आक्रामक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने कहा है कि वह अब संन्यास के बाद फ्रेंचाइजी क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन का प्रयास करेंगे। क्लासेन ने स्पष्ट किया है कि अब उनका एकमात्र लक्ष्य दुनिया भर की विभिन्न लीगों में जिन टीमों के लिए वे खेलते हैं, उनके साथ ट्रॉफी जीतना है।

क्लासेन ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, जिसके बाद वे फ्रेंचाइजी क्रिकेट में लगातार सक्रिय हैं। आईपीएल और द हंड्रेड के अलावा, वे एएस ए 20 में डरबन सुपर जायंट्स के लिए खेलते हैं। आईएलटी20 में गल्फ जायंट्स के साथ पदार्पण करने वाले हैं और पहली यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग में रॉटरडैम डॉकर्स का भी हिस्सा होंगे। दुनिया भर की अलग-अलग लीगों में खेलने और खुद को प्रबंधित करने के बारे में क्लासेन ने बताया, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने से मुझे इन प्रतियोगिताओं के बीच ब्रेक लेने की आजादी मिली है। इनमें से ज्यादातर प्रतियोगिताओं के बीच मुझे करीब एक महीने, डेढ़ महीने या दो महीने का समय मिल जाता है। उन्होंने आगे कहा कि इससे उन्हें खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से रीसेट करने, उन पहलुओं को समझने जिन पर काम करने की जरूरत है, और अगले टूनार्मेंट के लिए अपने शरीर को पूरी तरह से तैयार करने का पर्याप्त समय मिल जाता है।

एकदिवसीय में जगह नहीं बना पाने के लिए अपने को जिम्मेदार मानते हैं सूर्यकुमार

मुम्बई। भारतीय टी20 क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और अच्छी तकनीक के बाद भी एकदिवसीय टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाये और टी20 तक ही सीमित होकर रह गये। सूर्यकुमार ने अब इसका कारण बताया है। उनका कहना है कि इसके लिए वह स्वयं को ही जिम्मेदार मानते है। इस बल्लेबाज ने कहा है कि एकदिवसीय के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिये थी। वह नहीं कर पाये। सूर्यकुमार ने अपने करियर में 37 एकदिवसीय मैचों में खेलते हुए केवल 773 रन बनाए हैं। उन्होंने अंतिम बार एकदिवसीय मुकाबला 2023 विश्व कप का फाइनल था, जहां सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए वह केवल 18 रन ही बना पाये। उसके बाद वह टीम से बाहर हुए तो वापसी नहीं कर पाये। वहीं अब वह टी20 विश्वकप से भी बाहर हो गये हैं। 30 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने वाले सूर्यकुमार का मानना है कि अगर उन्हें 2016 के आसपास टीम इंडिया में मौका मिल जाता, तो शायद वे टेस्ट और एकदिवसीय क्रिकेट में एक अलग मुकाम

हासिल कर पाते।

सूर्यकुमार ने अपना एकमात्र टेस्ट मैच, जो 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। इसमें वह केवल 8 रन ही बना पाए थे। उस पारी के बाद वह टेस्ट टीम में जगह नहीं बना पायी। अपनी एकदिवसीय विफलताओं को लेकर उन्होंने कहा, यह टी20 की तरह ही सीमित ओवरों है पर मैंने इसमें उतनी मेहनत नहीं की, जितनी मुझे करनी चाहिए थी। मैं व्यक्तिगत रूप से यह स्वीकार करता हूँ कि मैं इस फॉर्मेट का फामुर्ला नहीं खोज पाया। उन्होंने आगे कहा, मैं जानता था कि मुझे नंबर 5 या 6 पर ही बल्लेबाजी मिलेगी, फिर भी मैंने इस प्रारुप को बेहतर ढंग से समझने या इसके अनुसार अपने खेल में बदलाव लाने के अधिक प्रयास नहीं किए, और इसका सीधा असर मेरे प्रदर्शन पर दिखा। सूर्यकुमार के अंतरराष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो, टी20 प्रारुप में उनकी बादशाहत साफ दिखती है। उन्होंने 113 टी20 मैचों में 3272 रन बनाए हैं, जिसमें उनके अंतरराष्ट्रीय करियर के सभी चार शतक शामिल हैं। इसके विपरीत, 37 एकदिवसय मैचों में उनके नाम 773 रन हैं, जिसमें उनका सर्वाधिक स्कोर 72 रन रहा। टेस्ट क्रिकेट में उनका एकमात्र अनुभव एक पारी का है, जहाँ वे सिर्फ 8 रन ही बना सके थे।

महिला एशिया कप में पाकिस्तान से मुकाबले को लेकर बोले बोले कोच अमोल मजूमदार

दुबई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को 5 सितंबर को एशिया कप में पाकिस्तान टीम से खेलना है। भारतीय टीम का लक्ष्य इस मैच को जीतकर पाक के खिलाफ अपने जीत के रिकार्ड को बनाये रखना होगा। भारतीय टीम के प्रदर्शन को देखते हुए वह इस मैच में जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। प्रशंसक भी इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

पाक से तनाव को देखते हुए पिछले कुछ टूनार्मेंटों से महिला टीम ने पाक खिलाड़ियों से दूरी बनाये रखी थी, अब देखना है कि एशिया कप में भी यही सिलसिला जारी रहता है या नहीं। वहीं इस मामले को लेकर भारतीय टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने कहा है कि हम मैदान पर सबसे अच्छा

क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं, और मैदान के बाहर की चीजों पर अधिक ध्यान नहीं देते। हम उस दिन सबसे अच्छा क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं, और जब हम वह मैच खेलेंगे तो इस बारे में बात करेंगे। उनके इस बयान से साफ होता है कि टीम का ध्यान बाहरी विवादों की जगह पर खेल में बेहतर प्रदर्शन पर रहेगा।

भारतीय टीम के हालिया टी20 फॉर्मेट प्रदर्शन को लेकर उठ रहे सवालों पर भी मजूमदार ने जवाब दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले छह महीनों में टीम के प्रदर्शन को लेकर चचाएं रही हैं, लेकिन उनका मानना है कि हम फॉर्म पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। हम जानते हैं कि इस टीम में सुधार की बहुत गुंजाइश है। टीम में युवा खिलाड़ी हैं। हम अच्छा और आक्रामक क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। कोच के बयान से भारतीय टीम की रणनीति और पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले खिलाड़ियों के मानसिक स्थिति का पता चलता है, जिसमें उनका पूरा जोर क्रिकेट और मैदान पर बेहतर प्रदर्शन पर है।

संन्यास के बाद भी धोनी की कमाई पर नहीं पड़ा है असर

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिह घोनी खेल से संन्यास के बाद भी मोटी कमाई कर रहे हैं। संन्यास के बाद धोनी की कमाई मुख्य रुप से विज्ञापन से हो रही है। वह कई बड़े ब्रांड से वह जुड़े हुए हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के अलावा भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआईक) से भी उन्हें पेशन मिलती है। धोनी के कई कारोबार भी है। वह खेती भी करते हैं। धोनी ने अपने शानदार करियर में भारत के लिए कुल 90 टेस्ट मैच खेले हैं। बोर्ड की मौजूदा पेंशन व्यवस्था के तहत, वे पूर्व पुरुष क्रिकेटर जिन्होंने 25 या उससे अधिक टेस्ट मैच खेले हैं, उन्हें हर महीने 70,000 रुपये की पेंशन दी जाती है। इस हिसाब से, धोनी भी इस श्रेणी में आते हैं और उन्हें हर महीने बोर्ड से 70,000 रुपये मिलते हैं। हालांकि, उनकी कुल कमाई के विशाल आंकड़े के मुकाबले यह रकम काफी छोटी है।

धोनी आईपीएल में चेन्नई सुपरकिंग्स से खेल रहे हैं। सीएसके ने 2026 सीजन के लिए ने उन्हें 4 करोड़ रुपये में रिटेन किया है। इसका मतलब है कि केवल आईपीएल अनुबंध से ही उन्हें एक सीजन के लिए 4 करोड़ रुपये मिलते हैं। यदि इस रकम को 12 महीनों के हिसाब से बांटा जाए, तो यह औसतन करीब 33.3 लाख रुपये प्रति महीने बैठती है। हालांकि, यह केवल एक औसत है क्योंकि आईपीएल की रकम वास्तव में पूरे सत्र में एक बार ही मिलती है। इसके अलावा उन्हें मैच के हिसाब से फीस भी मिलती है।

धोनी की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा ब्रांड एंडोर्समेंट जो बड़ी कंपनियों से है। 2026 की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी सालाना आय 75 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है, जिसमें आईपीएल, विज्ञापन और कारोबार से होने वाली कमाई सम्मिलित है। कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी अनुमान लगाती हैं कि 2025-26 के लिए उनकी अनुमानित कमाई लगभग 95 से 105 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। इनमें ब्रांड एंडोर्समेंट कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। विभिन्न मीडिया सूत्रों और विश्लेषणों के आधार पर बताया गया है कि धोनी हर महीने लगभग 6 से 8 करोड़ रुपये सिर्फ विज्ञापनों और व्यावसायिक गतिविधियों से कमाते हैं। यह आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूरी बनाने के बावजूद धोनी की ब्रांड वैल्यू और व्यावसायिक अपील लगातार मजबूत बनी हुई है।

रिकॉर्ड बुक भरकर ही मानेंगे वैभव सूर्यवंशी !

नई दिल्ली। वैभव सूर्यवंशी इस समय महज 15 साल के है, लेकिन आए दिन कोई न कोई रिकॉर्ड अपने नाम कर लेते हैं। इस समय वह दलीप ट्रॉफी में नॉर्थ जोन के लिए खेल रहे हैं। सेमीफाइनल में इस टीम का सामना सेंट्रल जोन से हो रहा है और इस मैच में वैभव ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बेंगलुरू के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले जा रहे इस मैच के दूसरे दिन सोमवार को वैभव ने अपने बल्ले का कमाल दिखाया और रिकॉर्ड अपने नाम किया।

मिडफील्डर रोड्री को लेकर रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी के बीच खींचतान जारी

मैड्रिड। यूरोपीय फुटबॉल में आजकल स्पेन के दिग्गज मिडफील्डर रोड्री हर्नांडेज के ट्रांसफर को लेकर रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी के बीच जोरदार खींचतान चल रही है। यह बहुचर्चित खिलाड़ी वर्तमान में ट्रांसफर बाजार में मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि रियल मैड्रिड उन्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है। हालांकि, इस सौदे में सबसे बड़ी बाधा मैनचेस्टर सिटी की उच्च मांग है, जो अपने इस स्टार खिलाड़ी को छोड़ने के लिए कम से कम 80 मिलियन यूरो की राशि की मांग कर रहा है। इसके विपरीत, रियल मैड्रिड ने अपनी अधिकतम पेशकश 60 मिलियन यूरो तक ही सीमित रखी है, जिससे दोनों क्लबों के बीच 20 मिलियन यूरो का बड़ा अंतर बना हुआ है।

मीडिया रिपोर्टों से मिली जानकारी के अनुसार, दोनों क्लबों के बीच अभी तक कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई है और यह गतिरोध जारी है। इस हाई-प्रोफाइल ट्रांसफर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आने वाले कुछ सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। फुटबॉल विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह सौदा संभव होना है, तो दोनों पक्षों को एक बीच का रास्ता खोजना होगा, जिसमें उन्हें अपनी-अपनी शुरूआती मांगों से कुछ समझौता करना पड़ सकता है। यह स्पष्ट है कि इस बड़े खिलाड़ी को हासिल करने के लिए रियल मैड्रिड को अपनी पेशकश बढ़ानी होगी, वहीं मैनचेस्टर सिटी को भी अपनी मांग में थोड़ी नरमी दिखानी पड़ सकती है।

गौरतलब है कि रोड्री हर्नांडेज को मौजूदा समय में दुनिया के सबसे भरोसेमंद और प्रभावशाली मिडफील्ड खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उन्होंने पिछले कई वर्षों से मैनचेस्टर सिटी के लिए बड़े-बड़े मुकाबलों में लगातार असाधारण प्रदर्शन किया है। उनकी सटीक पासिंग क्षमता, खेल की गति को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित करने का हुनर और रक्षात्मक मोर्चे पर उनकी अभेद्य मजबूती उन्हें किसी भी टीम के लिए एक अमूल्य संपत्ति बनाती है। इन्हीं असाधारण खूबियों के चलते रियल मैड्रिड अपने मध्य क्षेत्र को और अधिक मजबूत व स्थिर बनाने के लिए लंबे समय से रोड्री पर अपनी नजरें जमाए हुए है।

रोड्री का मौजूदा अनुबंध वर्ष 2027 की गर्मियों तक वैध है। इस अनुबंध की स्थिति रियल मैड्रिड को बातचीत में कुछ हद तक बढ़त दिला सकती है, क्योंकि यदि मैनचेस्टर सिटी समय रहते रोड्री के साथ एक नया और दीर्घकालिक अनुबंध हासिल नहीं कर पाता है, तो भविष्य में खिलाड़ी की बाजार कीमत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर पिकअप दौडेगी अब विदेशी सडकों पर

नई दिल्ली। स्वदेशी कंपनी महिंद्रा अब महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर पिकअप के साथ वैश्विक बाजारों में अपनी पैठ मजबूत करने की तैयारी में है। कंपनी का लक्ष्य साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका जैसे प्रमुख बाजारों में अपनी उपस्थिति बढ़ाना है। यह नया पिकअप, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिंद्रा लाइफस्टाइलर के नाम से जाना जाएगा, अप्रैल 2027 तक लॉन्च होने वाला है। कंपनी के ऑटो और फार्म सेक्टर्स के ईडी और सीईओ राजेश के अनुसार, यह पिकअप पूरी तरह से वैश्विक प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया है, और महिंद्रा आसियान देशों में भी प्रवेश करने पर विचार कर रही है, जहां पिकअप की भारी मांग है। यह नया पिकअप केवल विदेशी ग्राहकों के लिए ही नहीं, बल्कि भारतीय बाजार के लिए भी महत्वपूर्ण है, जहां एडवेंचर और कैंपिंग के शौकीनों की संख्या तेजी से बढ़ी है। महिंद्रा का मानना है कि यह लाइफस्टाइलर पिकअप ऐसे ग्राहकों के लिए एक आदर्श विकल्प होगा।

इसके साथ ही, महिंद्रा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) सेगमेंट में भी शानदार प्रदर्शन कर रही है, पिछले 16-17 महीनों में कंपनी की कुल एसयूवी बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी 0 प्रतिशत से बढ़कर सीधे 12 प्रतिशत पर पहुंच गई है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 में 57,472 इलेक्ट्रिक चार-पहिया वाहन बेचे, जो पिछले वर्ष की तुलना में चार गुना अधिक है। महिंद्रा बीई 6, एक्सईवी 9ई और एक्सईवी 9एस जैसी इलेक्ट्रिक कारों के सफल लॉन्च के बाद, अब कंपनी इस महीने के अंत तक बीई 6 स्पोर्टेक को भी बाजार में लाने जा रही है।

एक झटके में दूध 9 प्रति लीटर महंगा, कीमत 100 के पार

1 सितंबर से लगेगा महंगाई का झटका? : कब तक 102 लीटर बिकेगा दूध?

नई दिल्लो चीनी, गुड़, प्याज और अंडे सहित अन्य जरूरी चीजों की महंगाई के साथ ही अब दूध की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक ही झटके में दूध की कीमत 9 प्रति लीटर बढ़ गई है, जिसके बाद दाम 100 प्रति लीटर को पार कर गई है। बॉम्बे मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने बताया कि नई दरें 1 सितंबर 2026 से लागू हो रही हैं।

बाम्बे मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई और आसपास के महानगरीय सप्लाई नेटवर्क में दूध की थोक कीमत में 9 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। उनके मुताबिक नई कीमत 1 सितंबर 2026 से लागू होगी और यह दर अगले 6 महीने तक यानि 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेगी।। इसके बाद दूध का थोक भाव 93 से बढ़कर 102 प्रति लीटर हो जाएगा। ये आम लोगों के लिए एक साथ तगड़ी महंगाई का झटका होने वाला है।

क्यों बढ़ाई गई दूध की कीमत?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दूध की कीमत में यह बढ़ोतरी डेयरी फार्मर्स और तबेला संचालकों की बढ़ती लागत के कारण की गई है। डेयरी फार्मर्स के मुताबिक हरा चारा, चूनी (अनाज के छिलके), और खली जैसे जरूरी पशुआहार की लागत में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही परिवहन के खर्चे में भी भारी वृद्धि देखी गई है। पशुओं का खान-पान और रखरखाव महंगा होने से अगले 6 महीनों के लिए दूध की कीमत बढ़ाई गई है।

आम लोगों पर दिखेगा सीधा असर

मुंबई और आसपास के सप्लाई नेटवर्क में एक झटके में 9 प्रति किलो की बढ़ोतरी के चलते आम लोगों को महंगाई का तगड़ा झटका लग सकता है। स्थानीय खुदरा विक्रेता और लोकल डेयरी के साथ-साथ घरों में आने वाले दूध विक्रेता भी अपने दाम बढ़ा सकते हैं। सुबह की चाय ले कर त्योहारों में मिलने वाली मिठाइयों के दाम भी बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ दूध से बनने वाली अन्य चीजें जैसे दही, पनीर, और छाछ की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

बीआइआरसी 2026: दुनिया में बढ़ी भारत के चावल की मांग, 138 देशों के 3317 खरीदारों ने आयोजन के लिए कराया पंजीकरण

नईदिल्ली। भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस (बीआईआरसी) 2026 के लिए दुनिया भर से भारी रुचि देखी जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी में अक्तूबर में होने वाले इस सम्मेलन के लिए अब तक 138 देशों के 3,317 खरीदारों ने पंजीकरण कराया है। यह संख्या भारतीय चावल की किस्मों के प्रति बढ़ती वैश्विक मांग को दशार्ती है। यह सम्मेलन 23 से 25 अक्तूबर तक भारत मंडपम में आयोजित होगा।

इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन (आईआरईएफ) के उपाध्यक्ष देव गर्ग ने बताया कि इक्र्र्छ 2026 के प्रति प्रतिक्रिया भारत की ओर देख रहे वैश्विक बाजारों की रुचि जाहिर करती है। उनका लक्ष्य इस अंतरराष्ट्रीय भागीदारी को भारतीय चावल निर्यातकों के लिए नए व्यापार मार्गो, नए खरीदारों और दीर्घकालिक

कारोबारी संबंधों में बदलना है। पंजीकरणों का भौगोलिक विस्तार इस साल के सम्मेलन की एक प्रमुख विशेषता है, जिसमें पड़ोसी बाजारों, अफ्रीका, खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया के खरीदारों ने महत्वपूर्ण भागीदारी दिखाई है।

पंजीकरण के मामले में बांग्लादेश 336 खरीदारों के साथ देश-वार पंजीकरण में सबसे आगे है, इसके बाद बेनिन 179 और नाइजीरिया 177 खरीदारों के साथ हैं। संयुक्त अरब अमीरात से 145 खरीदार, जबकि नेपाल और फिलीपींस से प्रत्येक 137 खरीदार पंजीकृत हुए हैं। इथियोपिया में 127, सऊदी अरब में 125, और इंडोनेशिया व दक्षिण अफ्रीका में प्रत्येक 109 पंजीकरण हुए हैं। सेनेगल, इराक, सोमालिया, गिनी, यमन, कोटे डी आइवर, नाइजर, ऑस्ट्रेलिया, माली, मलयेशिया, घाना, अंगोला और केन्या जैसे अन्य बाजारों से भी पंजीकरण प्राप्त हुए हैं। आईआरईएफ ने कहा कि बीआईआरसी 2026 का उद्देश्य बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय रुचि को भारतीय चावल निर्यातकों के लिए नए व्यावसायिक अवसरों और दीर्घकालिक संबंधों में बदलना है।

गर्ग ने कहा कि बीआईआरसी 2026 को एक कारोबारी मंच के रूप में स्थापित किया जा रहा है। यह अंतरराष्ट्रीय खरीदारों और भारतीय निर्यातकों के बीच संपर्क को आसान बनाएगा। एप-सक्षम इ2इ मैचमेकिंग खरीदारों, निर्यातकों, मिल मालिकों और सेवा प्रदाताओं को लक्षित बैठकें निर्धारित करने की अनुमति देगा। ये बैठकें चावल की किस्मों, मात्रा, उत्पाद विनिदेर्शों और बाजार की आवश्यकताओं पर आधारित होंगी। इसका उद्देश्य सामान्य नेटवर्किंग से हटकर व्यावसायिक रूप से सार्थक कारोबारी जुड़ाव की ओर बढ़ना है। आयोजकों का मानना है कि यह भौगोलिक विविधता भारतीय निर्यातकों को अपने ग्राहक आधार का विस्तार करने में मदद कर सकती है।

चीनी एक सप्ताह में 294 रुपए महंगी, सरसों तेल 162 रुपए चढ़ा

नई दिल्ली। घरेलू थोक जिंस बाजारों में बीते सप्ताह चीनी 294 रुपए और सरसों तेल 162 रुपए प्रति क्विंटल महंगा हो गया। चावल, अधिकतर खाद्य तेल और दालों में भी तेजी रही। बीते सप्ताह मीठे के बाजार में गुड़ का औसत भाव 294 रुपये चढ़कर सप्ताहांत पर 5,911 रुपये प्रति क्विंटल रहा। इसमें पहले तीन दिन तेजी देखी गई जबकि अंतिम तीन दिन कीमतों में उतार देखा गया। इससे पहले के सप्ताह में चीनी 777 रुपये महंगी हुई थी।

गुड़ का भाव पिछले सप्ताह 310 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गया। यह एक सप्ताह पहले 323 रुपये महंगा हुआ था। सप्ताह के दौरान चावल की औसत कीमत 31 रुपये बढ़कर सप्ताहांत पर 4,134 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गयी। गेहूं 29 रुपये महंगा हुआ और 2,867 रुपये प्रति

क्विंटल बोला गया। आटे का भाव भी 15 रुपये चढ़कर 3,325 रुपये प्रति क्विंटल हो गया।

सप्ताह के दौरान उड़द दाल की औसत कीमत 44 रुपये और तुअर दाल की 35 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ी। मूंग दाल 19 रुपये और चना दाल 17 रुपये महंगी हुई। वहीं मसूर दाल में आठ रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट देखी गयी। बीते सप्ताह सरसों तेल का औसत भाव 162 रुपये और पाम ऑयल का 104 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गया।

रेलवे ने शहडोल को दी सौगात

शहडोल। कोरोना काल से बंद पड़ी बिलासपुर-इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस अब एक बार फिर वेंकटनगर रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह के निरंतर प्रयासों के बाद रेल मंत्रालय ने इस ठहराव को पुनः अपनी स्वीकृति दे दी है। बिलासपुर-कटनी रेल खंड के अंतर्गत आने वाला वेंकटनगर एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र है, और नर्मदा एक्सप्रेस के यहां रुकने से स्थानीय व्यापारियों, किसानों और आम यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

5 सितंबर को जनता दिखाएगी हरी झंडी

आगामी 5 सितंबर को इस ठहराव का औपचारिक शुभारंभ किया जाना है, जो जन-भागीदारी की एक अनूठी मिसाल बनेगा। दरअसल, इस ऐतिहासिक अवसर पर सांसद हिमाद्री सिंह क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहेंगी, इसलिए उनके स्थान पर स्थानीय ग्रामीण, व्यापारी और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ही ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

सांसद की अनुपस्थिति का कारण उनका एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय दौरा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नामांकन पर सांसद हिमाद्री सिंह को भारत-उज्बेकिस्तान युवा सांसद प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया गया है। वे 4 से 7 सितंबर तक उज्बेकिस्तान के चार दिवसीय दौरे पर रहेंगी।

कोरोना काल में बंद नर्मदा एक्सप्रेस का वेंकटनगर ठहराव फिर बहाल

मार्च 2026 में गठित इस संसदीय मैत्री समूह में देश के 543 सांसदों में से केवल तीन युवा सांसदों को चुना गया है, जिसमें शहडोल की सांसद का नाम भी शामिल है। आदिवासी समाज से आने वाली युवा नेत्री का यह चयन क्षेत्र के लिए एक बड़ी गौरव की बात है।

कूटनीतिक लिहाज से अहम है यह दौरा

यह उज्बेकिस्तान दौरा कूटनीतिक लिहाज से भी काफी अहम है, क्योंकि हाल ही में 30 अगस्त को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के सर्वोच्च राजकीय सम्मान 'ओली दराजली दोस्तलिक' (उच्चतम मित्रता आर्डर) से सम्मानित किया है। एक तरफ जहां सांसद ताशकंद जैसे वैश्विक मंच पर भारत और शहडोल का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, वहीं उनके प्रयासों से क्षेत्रीय विकास को रफ्तार देते हुए वेंकटनगर को ट्रेन ठहराव की यह बड़ी सौगात मिली है।

42 सेक्टरों की पड़ताल से बनेगा उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन का विकास रोडमैप

इंदौर। उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन के सुनियोजित और दीर्घकालीन विकास के लिए बड़ी कवायद शुरू हो गई है। रीजन में शामिल छह जिलों के मौजूदा संसाधनों, सुविधाओं और विकास की स्थिति का व्यापक आकलन किया जा रहा है। 42 प्रमुख सेक्टरों पर केंद्रित सिचुएशन एनालिसिस रिपोर्ट एक माह में तैयार हो जाएगी। इसके आधार पर आने वाले वर्षों के लिए मेट्रोपॉलिटन रीजन का विकास रोडमैप तय किया जाएगा। रिपोर्ट में यह स्पष्ट होगा कि वर्तमान में क्षेत्र में उपलब्ध संसाधन कितने पर्याप्त हैं और भविष्य की जरूरतों के लिए किन क्षेत्रों में नए निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी।

उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। इसमें शामिल इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, शाजापुर और रतलाम जिलों के तहसील और गांवों का क्षेत्रफल निर्धारित किया

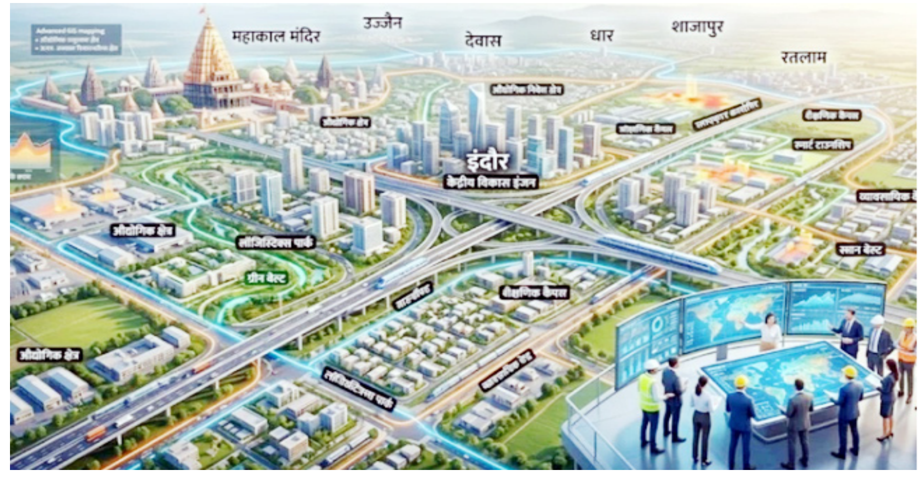

गया है। कुल 16 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले इस रीजन में 38 तहसीलें और 2781 गांव शामिल हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहां की आबादी 75.34 लाख थी, जो अब बढ़कर करीब 90 से 95 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। इंदौर विकास प्राधिकरण को कंसल्टेंट एजेंसी द्वारा दो माह पहले प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है और इसका प्रजेंटेशन भी दिया गया था। इसके बाद सिचुएशन रिपोर्ट का काम चल रहा है, जो आगामी माह तक पूरा हो जाएगा।

कृषि, उद्योग और कनेक्टिविटी पर फोकस

सिचुएशन एनालिसिस के दौरान कृषि गतिविधियों, औद्योगिक विकास, सड़क और रेल कनेक्टिविटी, उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक इकाइयों और हरित क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही अन्य विभागों की मौजूदा योजनाओं और उपलब्ध सुविधाओं का आकलन भी होगा। इस सर्वे से यह पता लगाया जाएगा कि मेट्रोपॉलिटन रीजन के किन हिस्सों में बुनियादी सुविधाएं पर्याप्त हैं और किन क्षेत्रों में विकास की जरूरत सबसे अधिक है। बढ़ती आबादी को देखते हुए आवास, परिवहन, जलापूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास के लिए भविष्य की जरूरतों का भी अनुमान लगाया जाएगा।

अगले चरण में विकास और निवेश प्लान

पहले चरण में रीजन की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है और अब सिचुएशन एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसके बाद रीजनल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार किया जाएगा। इसमें रीजन के विकास का दीर्घकालीन विजन, आगामी विकास रणनीति, निवेश की योजना और मौजूदा संसाधनों के बेहतर उपयोग का खाका शामिल होगा। इसके बाद प्रस्तावित मेट्रोपॉलिटन रीजन का ड्राफ्ट तैयार कर टोपोग्राफिक सर्वे कराया जाएगा और विभिन्न परियोजनाओं की डीपीआर बनाई जाएगी।

नए रेल रूट होंगे अहम

उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन में आने वाले वर्षों में कई नए रेल रूट तैयार हो जाएंगे। इसमें टीही-धार, धार-दाहोद, महू-मनमाड़ और मांगलिया-बुधनी जैसे प्रस्तावित रेलवे रूट भी भविष्य की कनेक्टिविटी योजना में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

रीजन में चार नगर निगम, सात नगर पालिकाएं, 25 नगर पंचायत और महू कैंटोनमेंट बोर्ड शामिल हैं। यह पूरी कवायद रीजन क्षेत्र को एकीकृत, आधुनिक और निवेश के अनुकूल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की दिशा तय करेगी।

अवैध हथियारों के साथ 14 बदमाश गिरफ्तार, पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में आपराधिक गतिविधियों और अवैध हथियारों पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने के मकसद से एसएसपी धर्मवीर सिंह की देखरेख में ऑपरेशन ईगल चलाया गया। एएसपी सुजावल जग्गा, एएसपी शिवेश सिंह बघेल और एएसपी (ग्रामीण) जयराज कुबेर की अगुवाई में सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए कि वे अवैध हथियार रखने वालों और सोशल मीडिया पर हथियार दिखाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इसी कड़ी में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जिलेभर में एक साथ छापेमारी की और 14 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से बरामद पिस्टल, कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

दूध के दाम बढ़ाने के लिए देपालपुर में भी किसानों ने दी हड़ताल की चेतावनी

इंदौर। दूध के नए खरीदी दाम तय होने से पहले किसानों ने दाम बढ़ाने को लेकर बिगुल बजा दिया है। संभागायुक्त और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के बाद अब किसान लगातार बैठक कर एकजुट हो रहे हैं। शनिवार को सांवेर क्षेत्र में बैठक हुई थी और रविवार को देपालपुर क्षेत्र के दूध उत्पादक किसानों ने बड़ी बैठक की। इसमें दूध के दाम बढ़ाने को लेकर किसानों ने सर्वसम्मति से हुंकार भरी।

सभी ने एक होकर आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया। जिला ग्रामीण दूध उत्पादक किसान संगठन द्वारा सांवेर के बाद अब

देपालपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम करजोदा में किसानों की एक बैठक हुई। बैठक में क्षेत्र के हजारों दुग्ध उत्पादक किसान अपनी मांगों को लेकर एकजुट दिखे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रमुख किसान नेता दिलीप सिंह पंवार और हंसराज मंडलोई ने दुग्ध उत्पादक किसानों की ज्वलंत समस्याओं और मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।

उन्होंने कहा कि जब हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं तो किसानों के दूध की कीमत बढ़ाने में देरी क्यों की जा रही है? किसानों से दूध की खरीदी 12 रुपये प्रति फैट के अनुसार की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों से खरीदी दाम नहीं बढ़ाए गए तो हड़ताल की जाएगी। बैठक में संगठन के वरिष्ठ साथी चंदनसिंह बडवाया, अशोक चौहान, मुकेश चौहान, दिनेश चौहान, अंतरसिंह राठौर, कैलाश पटेल, सत्यनारायण चौहान, आनंद सिसोदिया आदि किसान मौजूद रहे।

मातम में बदलीं खुशियां, जबलपुर में बाइक-ई-रिक्शा की भीषण भिड़ंत

महिला की मौत और पति-बच्चे समेत नौ घायल

जबलपुर। सिहोरा थाना क्षेत्र के ग्राम दर्शनी में रविवार को बाइक और ई-रिक्शा की जोरदार भिड़ंत में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसके पति और एक बच्चे समेत नौ लोग घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ, जब एक दंपती रक्षाबंधन का पर्व मनाने के बाद बाइक से मायके से अपने घर लौट रहा था। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार तीन लोग सड़क पर दूर जा गिरे, जबकि ई-रिक्शा पलटने से उसमें सवार कई लोग दब गए। मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को बाहर निकालकर सिहोरा अस्पताल भेजा गया। वहां डॉक्टरों ने बाइक सवार महिला को मृत घोषित कर दिया। उसके पति और बच्चे की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल अस्पताल जबलपुर रेफर किया है।

सिहोरा पुलिस के अनुसार ग्राम पौड़ा निवासी शुभम कोल (30) रक्षाबंधन के अवसर पर पत्नी प्रीति कोल (20) के साथ उसके मायके ग्राम सिलौड़ी गया था। पर्व के बाद रविवार को शुभम पत्नी प्रीति के साथ बाइक से वापस पौड़ा लौट रहा था। उनके साथ शुभम का ममेरा भाई अनुराग (11) भी बाइक पर सवार था। पुलिस के अनुसार बाइक सवार दर्शनी के पास पहुंचे ही थे कि

सामने से आ रहे ई-रिक्शा से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि शुभम, प्रीति और अनुराग बाइक से उछलकर सड़क पर दूर जा गिरे। तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

दूसरी ओर, टक्कर के बाद ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। उसमें सवार सुधा रावत (18), जानकी रावत (19), नेहा कोल (26), सुखवंती बाई कोल (55), दुर्गा कोल (7), अभि कोल (6) और राजकुमार कोल (35) घायल हो गए। ई-रिक्शा पलटने के कारण कुछ यात्री उसके नीचे दब गए। क्षतिग्रस्त वाहन और मौके पर खड़े लोग।

चीख-पुकार सुनकर दौड़े लोग, घायलों को वाहन से निकाला

हादसे के बाद आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। सड़क से गुजर रहे लोग तत्काल मौके पर पहुंचे और घायलों को ई-रिक्शा के नीचे से बाहर निकाला। सूचना मिलने पर पुलिस और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच गई। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सिहोरा अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने प्रीति कोल को परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। वहीं उसके पति शुभम और अनुराग की हालत गंभीर होने पर दोनों को मेडिकल अस्पताल जबलपुर रेफर कर दिया गया। दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। ई-रिक्शा में सवार अन्य घायलों को सिहोरा अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। उपचार के बाद उनकी हालत सामान्य होने पर उन्हें अस्पताल से जाने दिया। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। वाहन चालकों और प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी ली जा रही है।

ग्वालियर में भादौ के पहले दो दिन नहीं बरसे बादल

अब हल्की से मध्यम बारिश की संभावना, पारा भी लुढ़केगा

ग्वालियर। भादौ महीने के शुरू हुए दो दिन बीत चुके हैं लेकिन जिले में बारिश नहीं हुई और शुरूआती दो दिन सूखे बीत गए। आसमान में बादलों की आवाजाही से जरूर तापमान में गिरावट देखने को मिली है। अब तापमान 3.2 डिग्री गिरकर 31.3 डिग्री सेल्सियस पर आ चुका है।

हालांकि, इस दौरान लोगों को गर्मी से और उमस से राहत जरूर मिली है। लेकिन इस साल बाकी जिलों और राज्यों की तुलना में ग्वालियर में बारिश कम हुई है। इस साल 602 मिमी वर्षा अब तक दर्ज हुई है, जबकि बीते साल 2025 में 900 मिमी वर्षा दर्ज की गई थी। मौसम विज्ञान केन्द्र का कहना है कि आगामी दो दिनों में शहर में बारिश देखने को मिलेगी लेकिन यह हल्की से मध्यम हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक, 31 अगस्त से लेकर एक सितंबर तक आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और इस दौरान बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा तेज हवाओं से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी।

एमपी हाईकोर्ट ने सीधी कॉलेज के कर्मचारियों का आदेश किया निरस्त

15 साल नौकरी फिर भी नहीं मिला स्थाई दर्जा

जबलपुर : केवल लंबे समय तक काम करने से किसी कर्मचारी को स्थाई कर्मी बनने का अधिकार नहीं मिल जाता। जनभागीदारी समिति द्वारा नियुक्त व्यक्ति भी केवल नियुक्ति के आधार पर राज्य सरकार का नियमित कर्मचारी नहीं बन सकता।

हाई कोर्ट की युगलपीठ ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए सीधी के संजय गांधी स्मृति शासकीय महाविद्यालय के 11 कर्मचारियों को स्थाई कर्मी का दर्जा देने संबंधी एकलपीठ का आदेश निरस्त कर दिया।

दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक

प्रशासनिक न्यायाधीश आनंद पाठक व न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की युगलपीठ ने राज्य शासन की रिट अपील स्वीकार करते हुए कहा कि संबंधित कर्मचारियों को सरकारी नीति का लाभ लेने के लिए निर्धारित कट-आफ तिथि से निरंतर सेवा का विश्वसनीय दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक था।

कर्मचारियों ने दावा किया था कि वे 15 वर्ष से अधिक समय से महाविद्यालय में कार्यरत हैं और सामान्य प्रशासन विभाग की सात अक्टूबर, 2016 की नीति के तहत स्थाई कर्मचारी का दर्जा पाने के हकदार हैं। सिंगल बेंच ने उनके पक्ष में आदेश दिया था, जिसे उच्च शिक्षा विभाग ने चुनौती दी।

युगलपीठ ने पाया कि कर्मचारी 16 मई, 2007 से निरंतर सेवा का ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके। रिकार्ड में केवल अक्टूबर 2010 के बाद के लेबर चार्ज बिल उपलब्ध थे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जनभागीदारी समिति को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नियमित पद सृजित करने अथवा सरकारी नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है। समिति द्वारा किसी व्यक्ति की सेवाएं लेने मात्र से उसे नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल जाता।

कट-ऑफ तिथि से सेवा का प्रमाण जरूरी

हाई कोर्ट ने कहा कि स्थाई कर्मी का दर्जा पाने के लिए केवल लंबी सेवा का दावा पर्याप्त नहीं है। संबंधित नीति की शर्तों को पूरा करने के साथ निर्धारित कट-आफ तिथि से निरंतर सेवा का ठोस और विश्वसनीय दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना भी आवश्यक है।

गुस्साए ठेला चालक ने पेट-सीने और माथे पर चाकू से किए वार

जबलपुर : शहर के गोहलपुर थाना अंतर्गत दमोहनाका स्थित शराब दुकान के पास देर रात आपसी विवाद ने खूनी रूप ले लिया। मामूली बात पर शुरू हुए झगड़े में बीच-बचाव करने पहुंचे एक 38 वर्षीय प्रापर्टी ब्रोकर पर ठेला लगाने वाले एक युवक ने चाकू से ताबड़तोड़ कई जानलेवा वार कर दिए। इस अचानक हुए हमले में ब्रोकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डाक्टरों के अनुसार उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, जबकि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर चल रहे काम की वजह से मालवा एक्सप्रेस और अमृतसर-इंदौर ट्रेन रहेंगी प्रभावित

इंदौर। उत्तर रेलवे दिल्ली मंडल के हजरत निजामुद्दीन-पलवल रेल खंड पर फरीदाबाद स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक दो और तीन पर निर्माण कार्य के लिए ब्लाक प्रस्तावित है। इस कारण पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा।

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार कुछ ट्रेनों का ठहराव अस्थायी रूप से निरस्त किया गया है। 31 अगस्त से 14 अक्टूबर तक डॉ. अंबेडकर नगर से चलने वाली डॉ. अंबेडकर नगर-श्री

माता वैष्णो देवी कटड़ा मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 31 अगस्त से 14 अक्टूबर तक लक्ष्मीबाई नगर से चलने वाली लक्ष्मीबाई नगर-योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस प्रभावित रहेगी।

एक सितंबर से 15 अक्टूबर तक अमृतसर से चलने वाली अमृतसर-इंदौर एक्सप्रेस, एक सितंबर से 15 अक्टूबर 2026 तक श्री माता वैष्णोदेवी कटड़ा से चलने वाली श्री माता वैष्णोदेवी कटड़ा-डॉ. अंबेडकर नगर मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक सितंबर से 15 अक्टूबर तक ऊना हिमाचल से चलने वाली ऊना हिमाचल-इंदौर एक्सप्रेस प्रभावित रहेगी। रेलवे के अनुसार इंदौर से चलने वाली उक्त ट्रेनों के यात्रियों को असुविधा न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति की जानकारी ले लें।

पंद्रह दिन से इलाज करा रही 10 वर्षीय बच्ची की मौत, हर्ष क्लीनिक में स्वजन का हंगामा

इंदौर। खातीवाला टैंक स्थित हर्ष क्लीनिक में इलाज के दौरान 10 वर्षीय बच्ची की मौत के बाद रविवार देर रात विवाद और हंगामा हो गया। आक्रोशित स्वजन सहित अन्य बड़ी संख्या में जूनी इंदौर थाने पहुंचे और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए संबंधित डाक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

बच्ची की पहचान गणेश नगर, खंडवा नाका निवासी दिव्यांशी पुत्री मनोज सोलंकी के रूप में हुई है। स्वजन के अनुसार बच्ची को पेट दर्द की शिकायत थी और करीब 15 दिनों से उसका इलाज

हर्ष क्लीनिक में डॉ. श्रीचंद बागैचा से कराया जा रहा था। रविवार दोपहर उसे दोबारा क्लीनिक लाया गया, जहां इंजेक्शन लगाने और बाटल चढ़ाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। कुछ घंटे बाद बच्ची की मौत हो गई।

रेफर नहीं करने पर उठाए सवाल

बच्ची के पिता और डॉक्टर के बीच फोन पर हुई कथित बातचीत का ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें क्लीनिक में आईसीयू सुविधा नहीं होने की बात कही जा रही है। स्वजन का कहना है कि गंभीर स्थिति की जानकारी मिलती तो वे बच्ची को तत्काल अन्य अस्पताल में भर्ती कराते। मामले में जूनी इंदौर पुलिस को स्वजनों ने शिकायती आवेदन दिया। जूनी इंदौर थाना प्रभारी का कहना है कि स्वजन ने खातीवाला टैंक स्थित हर्ष क्लीनिक में उपचार में लापरवाही को लेकर आवेदन दिया है। इसके आधार पर मामले की जांच की जाएगी। गौरतलब है कि हर्ष क्लीनिक में 14 बेड की सुविधा है और इसका लाइसेंस डॉ. ज्ञान एस. पंजवानी के नाम पर है। वर्ष 2025 में भी यहां इलाज के दौरान एक महिला की मौत के मामले में पुलिस प्रकरण दर्ज कर चुकी है। नए मामले के बाद क्लीनिक में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं और इलाज की व्यवस्था को लेकर फिर सवाल खड़े हो गए हैं।

स्वामी, प्रकाशक : अली आदिल खान द्वारा साईं प्रिंटिंग प्रेस डी 85 सेक्टर 8, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर 201301 से मुद्रित और एच 41 ए, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, दक्षिण पूर्व दिल्ली 110025 से प्रकाशित। संपादक : अली आदिल खान
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।